फरवरी - 2025 वर्ष : 10 अंक : 2

मीडिया मैप

उदार जनतंत्र का सजग प्रहरी

शुल्क : 50

हम क्यों...

मीडिया मैप एक वैचारिक पत्रिका है। हमारे समाज के नीतिपरक और मूल्यनिष्ठ बिन्दु तथा इनसे जुड़ाव रखने वाले आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक मुद्दे इसकी विषयवस्तु है। मीडिया मैप की संपादकीय नीति उदारवादी, आधुनिक, प्रगतिशील व सर्व धर्म समभाव की भावना पर आधारित है। मीडिया मैप हमारे बहुलतावादी समाज की विविधताओं से सृजित समस्त सोच, विचार, दृष्टिकोण, मूल्य और मान्यताओं को अपने में समाहित करने का एक प्रयास है । हमारा उद्देश्य वैज्ञानिक सोच द्वारा समाज से जुड़े मूल मुद्दों पर एक प्रबुद्ध जनमत विकसित करना है जिससे देश में संकुचित मानसिकता और आपसी टकराव से ऊपर उठकर एक उच्चस्तरीय विचार-विमर्श का वातावरण तैयार हो सके।

मीडिया मैप

सलाहकार मंडल
डॉ. रामजीलाल जांगिड
डॉ बलदेवराज गुप्त
डॉ जॉन दयाल
डॉ गौहर रजा
मंगल सिंह आजाद

संपादक :**प्रो प्रदीप माथुर**
संयुक्त संपादक : **डॉ सतीश मिश्रा**
सहयोगी संपादक : **प्रो शिवाजी सरकार**
विशेष प्रतिनिधि : **राजीव माथुर**
मुख्य सह-संपादक :**प्रशांत गौतम**
सह-संपादक : **अंकुर कुमार**
लखनऊ संवादाता :**ज़ेबा हसन**
पटना संवादाता :**अजय यायावर**
रायपुर संवादाता :**संदीप कुमार सिंह**

मुख्य प्रबंधक :**जगदीश गौतम**
विधि परामर्शदाता :**संजय माथुर**

पंजीकृत कार्यलय
2325, सेक्टर - डी , पॉकेट - 2 , वसंतकुंज , नई दिल्ली

कार्यालय
69 ज्ञानखंड-4 इंदिरापुरम गाजियाबाद-201014

दूरभाष - **9810385757 / 9910069262**

एम बी के एम फाउंडेशन प्रकाशन

ईमेल-**editor@mediamap.co.in**

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक प्रदीप माथुर द्वारा लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली से मुद्रित एवं मकान नंबर 70, ज्ञानखंड 4, इंदिरापुरम, जनपद-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित. सभी विवादों का निस्तारण जिला न्यायालय गाजियाबाद होगा ।

लेखों में उल्लेखित विचार लेखक के अपने हैं। लेखों और विचारो को लेकर विवाद होने पर पत्रिका के संपादक और प्रकाशक, मुद्रक इसके लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जिला मुख्यालय गाज़ियाबाद ही होगा। इस पत्रिका से जुड़े सभी पदाधिकारी, सहयोगी और लेखक अवैतनिक हैं। पीआरबी एक्ट के तहत अंतर्गत संपादक प्रो प्रदीप माथुर उत्तरदायी है।

संपादकीय
पत्र पाठको के
एक झलक पिछले अंक की
विचार प्रवाह

केंद्रीय बजट विशेष		
आर्थिक मंदी और ट्रम्प का रुख वित्त मंत्री के लिए बड़ी चुनौतियां	प्रो शिवाजी सरकार	8
कृषि क्षेत्र पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता	प्रो शिवाजी सरकार	10
भारत को एक नई अर्थव्यवस्था की जरूरत है	प्रो शिवाजी सरकार	11
दिल्ली चुनाव		
भारतीय राजनीति के विलक्षण पुरुष अरविंद केजरीवाल	प्रो प्रदीप माथुर	14
चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठते प्रश्न	डॉ. मुजफ्फर हुसैन ग़ज़ाली	16
कुंभ त्रासदी		
आस्था के पर्व को राजनैतिक लाभ, और व्यवसाय बनाने का परिणाम	प्रशांत गौतम	18
कुंभ और गंगा सागर: राजनीतिक टकराव का कारण बने दो पवित्र आयोजन	प्रभजोत सिंह	20
देश-विदेश		
भारत और राष्ट्रपति ट्रंप की नई अर्थव्यवस्था	गोपाल मिश्रा	21
क्या कनाडा का प्रधान मंत्री भी भारतवंशी होगा?	प्रभजोत सिंह	23
जनवरी 30 : महात्मा गांधी बलिदान दिवस		
स्वतंत्रता आंदोलन में गांधीजी के योगदान को कमतर आंकने का प्रयास	प्रो राम पुनियानी	25
बापू की सरलता और सादगी तथा यह वैभव और प्रदर्शन की संस्कृति	जगदीश गौतम	26
फरवरी 4: विश्व कैंसर दिवस		
कैंसर रोग की चिकित्सा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता	पवन सिंह	27
श्रद्धांजलि		
अनूप श्रीवास्तव जो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे	रामकिशोर उपाध्याय	29
व्यंगकार अनूप और उनके कल्लू मामा	गोपाल मिश्रा	31
सोशल मीडिया से		
हास्य व्यंग : क्यों केवल भारत में ही होता है पुर्नजन्म		33
कथा साहित्य		
सुन्दर फूलों का रहस्यमय गुच्छा	दिनेश नारायण वर्मा	34
अंदाज़-ए-लखनऊ		
समय की पुकार गंगा जमनी तहजीब	डॉ सतीश मिश्रा	36
लखनऊ काफी हाउस और बैठकबाजी की अनोखी विरासत	प्रदीप कपूर	37
मक्खन मलाई का जादू: जुबान के साथ आत्मा में भी घुल जाती है मिठास	ज़ेबा हसन	38

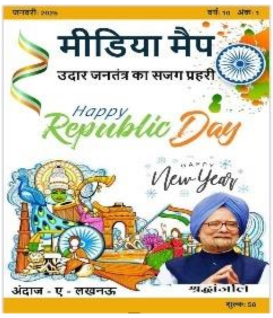

एक झलक पिछले अंक की

लोकतांत्रिक विमर्श की वापसी की आशा लिए आया नया वर्ष

*गया साल 2024 इतिहास का हिस्सा बन गया है। इस वर्ष को लोकतंत्र के लिए उम्मीद की नज़र से देखा जाएगा। हालाँकि अमेरिका, जर्मनी और अन्य देशों के लोग ने अपनी समस्याओं का समाधान दक्षिणपंथी विचारधारा में देखा है। वहीँ दुनिया भर से लोगों ने इजराइल की क्रूरता के खिलाफ आवाज भी उठाई। लम्बे संघर्ष के बाद सीरिया से तानाशाही का अंत हुआ, जनता के विरोध के कारण बांग्लादेश की निरंकुश शासक को देश छोड़कर भागना पड़ा। - **डॉ मुजफ्फर हुसैन ग़ज़ाली***

संवैधानिक शासन के 75 साल बाद कहां हैं हम

*भारत की संसद ने दो दिन तक देश के संविधान पर चर्चा की. विपक्षी नेताओं ने कहा कि हमारे संविधान में समाज के कमज़ोर वर्गों और धार्मिक अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए अनेक प्रावधान हैं मगर उसके बावजूद ये वर्ग परेशानहाल हैं. मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया है. - **प्रो राम पुनियानी***

डॉ. अंबेडकर की दलित सबलीकरण की विरासत और भाजपा

*डॉ.बीआर अंबेडकर भारत के उत्पीड़ित समुदायों के मुक्तिदाता और मुक्तिदाता बने हुए हैं। हालांकि, उन्हें दो राजनीतिक दलों के बीच में बांधने की कोशिशें उनकी विरासत की सतही और स्वार्थी समझ को दर्शाती हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राज्यसभा में दिया गया बयान बेहद आपत्तिजनक था, जो दलितों के दावे और सशक्तिकरण से असहज लोगों की हताशा को दर्शाता है। - **विद्या भूषण रावत***

कॉर्पोरेट कार्यशैली में पारदर्शिता और जनहित की आवश्यकता

*अडानी प्रकरण से पता चलता है कि कॉर्पोरेट महत्वाकांक्षा और सार्वजनिक जवाबदेही के बीच संतुलन बनाने की तत्काल आवश्यकता है। निर्णायक रूप से कार्रवाई करने में विफलता से भारत की वैश्विक आर्थिक प्रतिष्ठा और निवेशकों के विश्वास को और नुकसान पहुंचने का खतरा है। नैतिक कॉर्पोरेट प्रशासन सुनिश्चित करना, पारदर्शिता बनाए रखना और व्यावसायिक प्रथाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना विश्वास बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण है। संसद सदस्यों को भी आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए कॉर्पोरेट जवाबदेही को प्राथमिकता देनी चाहिए। - **प्रो शिवाजी सरकार***

क्या अब अमेरिका और कनाडा में बसना एक दिवास्वप्न होगा

*उत्तरी अमेरिका को अपना नया घर बनाने की इच्छा रखने वालों के लिए चीजें शायद वर्ष 2025 में उतनी अच्छी नहीं रही हैं। जनवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होगा जब डोनाल्ड ट्रम्प व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस में वापस लौटेंगे। कनाडा भी एक नये प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी में है। कनाडा और अमेरिका दोनों ने दक्षिण एशिया से और विशेष रूप से भारत से वर्ष 2024 में रिकॉर्ड आव्रजन देखा, यह अब समाप्त होने वाला है और अपने पीछे मीठी और खट्टी यादें छोड़ रहा है। उन लोगों का भविष्य अनिश्चित है जिनके पास अमेरिका या कनाडा में रहने के लिए कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने उन सभी लोगों को निर्वासित करने के अपने इरादे को कोई स्पष्ट किया है जिनके पास अमेरिका में रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। - **प्रभजोत सिंह***

सामाजिक-मानवीय आधार पर शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन की आवश्यकता

*शिक्षा का स्वरूप और पढ़ाये जाने वाले विषय सदा से सामाजिक, आर्थिक और कार्यालयी (राजकीय) आवश्यकताओं के पूर्त्यर्थ गढ़े भी जाते रहे हैं और उसका विस्तार भी इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के हिसाब से होता रहा है। प्राचीन काल में धर्मशास्त्र, व्याकरण, अस्त्र-शस्त्र संचालन आदि सीमित विषयों की शिक्षा तद् युगीन सीमित सामाजिक-आर्थिक-राजकीय आवश्यकताओं के अनुरूप थी। चूँकि आर्थिक और राजकीय गतिविधियाँ सीमित थीं, इस कारण शिक्षित-प्रशिक्षित लोगों की माँग भी कम थी। शिक्षित-प्रशिक्षित लोगों की माँग कम थी, इसलिए शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाएँ भी कम थीं। जो थीं भी, वे अनौपचारिक थीं। - **डॉ. अनिल कुमार रॉय***

भ्रष्ट परीक्षा प्रणाली की प्रताड़ना भुगतते छात्र

*बिहार में पेपर लीक एक सामान्य प्रचलन हो गया है। वह भी उस दौर में, जब बिहार में नीतीश कुमार पिछले 19 वर्षों से सुशासन के नाम पर राज कर रहे हैं। सवाल उठता है कि लगातार पेपर लीक होने के बावजूद इतने बड़े स्तर पर बहाली कैसे हो जाती है? सरकार आखिर इस लीक को रोक पाने में सफल क्यों नहीं हो रही है? बिहार के युवाओं को हर एक लीक के बाद आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है। लेकिन, बिहार के नेताओं का साथ क्यों नहीं मिल पाता? पेपर लीक का मामला मेनस्ट्रीम मीडिया में प्राइम डिबेट का हिस्सा क्यों नहीं होता? हर पेपर लीक के बाद सरकार के नौकरशाह इसकी लीपापोती में क्यों जुट जाते हैं? आखिर पेपर लीक से किसके हितों को साधा जा रहा है? क्या परीक्षा माफिया इतने मजबूत हैं कि वो सरकार पर दबाव बनाने में सफल हो जाते हैं कि उनके खिलाफ़ कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो पाती? अगर हाँ, तो इन माफियाओं का एक मजबूत गठजोड़ है सरकार एवं सरकारी तंत्रों के साथ। - **डॉ. नीरज कुमार***

साहसी निर्णय लेने वाला एक सौम्य व्यक्ति

*पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन के बाद मीडिया और सोशल मीडिया में उनके बारे में काफी कुछ लिखा और कहा गया। उन पर एक कार्यक्रम में एंकर ने मुझसे पूछा कि डॉ. मनमोहन सिंह की पहले और उनके बाद दो विपक्षी दल के प्रधान मंत्री रहे? दोनों के कार्यकाल के दौरान आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हुई। आप उनकी तुलना किससे करना चाहेंगे अटल बिहारी वाजपेई से या नरेंद्र मोदी से? - **प्रो प्रदीप माथुर***

****

संपादकीय

सभ्य, शालीन राजनैतिक विमर्श की आवश्यकता

दिल्ली के चुनाव का जो भी परिणाम हो, एक बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि वास्तव में हार राजनीतिक शालीनता और सभ्य राजनीतिक आचरण की ही होगी। दिल्ली का चुनाव जिस व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप और कीचड़ उछालने वाले गंदे और शोरगुल वाले प्रचार और हिंसक घटनाओं के साथ हो रहा है, उसने दलगत राजनीति के उस निम्न स्तर को छुआ है जिसकी हमारे संविधान निर्माताओं ने कल्पना भी न की होगी। पिछले सत्र में हमारे संसदीय विमर्श में पहले ही नरम भाषा, संतुलित अभिव्यक्ति और हास्य को तिलांजलि दे दी गई थी, अब हमने इस चुनाव प्रचार में असभ्य व्यवहार और असभ्य भाषा के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। प्रेस ने भी इन गंदे बयानों को बढ़ा-चढ़ाकर रिपोर्ट किया, जिससे वातावरण और भी दूषित हो गया है।

शायद अधिकांश पत्रकार सोचते हैं कि इन बदसूरत बातों के बारे में लिखना ही रिपोर्टिंग है। यहां दो प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न यह है कि हमारे राजनीतिक नेता और सांसद, जिनमें से कुछ काफी वरिष्ठ और महत्वपूर्ण पदों पर हैं, इस तरह का व्यवहार क्यों करते हैं। शायद उन्हें लगता है कि अपने राजनीतिक करियर में आगे बढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इससे उनके राजनीतिक आकाओं को खुशी मिलेगी और उन्हें मीडिया में सुर्खियाँ भी मिलेंगी।

शायद वे सही हैं। चाहे वे गिरिराज सिंह या अनुराग ठाकुर जैसे कैबिनेट मंत्री हों, हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे मुख्यमंत्री हों, कंगना रनौत या साध्वी प्रज्ञा भारती जैसे सांसद हों या नूपुर शर्मा जैसे पार्टी पदाधिकारी हों, उन पर लगाम लगाने या उन्हें रोकने का बजाए के शीर्ष नेतृत्व ने कभी कोई प्रयास नहीं किया। इससे उनको अनर्गल बातें कहने का और भी प्रोत्साहन मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने शब्दों के चयन में बहुत ही असावधान हैं। शायद भाजपा नेतृत्व को लगता है कि चुनाव जीतने और सत्ता में बने रहने के लिए, तब तक सब कुछ जायज है।

लेकिन क्या वास्तव में चुनाव जीतने और सत्ता की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए इस तरह का गंदा, आक्रामक और बेलगाम व्यवहार ज़रूरी है? अगर हम अपने लोकतांत्रिक शासन के शुरुआती दौर को भूल भी जाएँ और पिछले तीस सालों पर नज़र डालें तो हम अपने देश में उच्च राजनीतिक पदों पर कुछ बेहद सुसंस्कृत, सभ्य और परिष्कृत व्यक्ति देख सकते हैं। इनमें कांग्रेस में पीवी नरसिंह राव, अर्जुन सिंह, एनडी तिवारी, डॉ. मनमोहन सिंह और माधव राव सिंधिया और भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह, भैरों सिंह शेखावत, सुषमा स्वराज, यशवंत सिन्हा और अरुण जेटली शामिल थे। क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय दलों में भी सभ्य और परिष्कृत नेताओं की कमी नहीं थी।

जिस व्यक्ति ने सभी से सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया, वह सरल और सहज एपीजे अब्दुल कलाम थे, जो भारत के राष्ट्रपति के उच्च पद पर अपनी विशेषता के अनुसार विनम्र बने रहे। उनके बाद दूसरे स्थान पर प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह थे, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भी हृदय से एक शिक्षक बने रहे।

मोदी के इन वर्षों में भी, जब वे सार्वजनिक बहस में इतना गिर गए हैं, हमारे पास एक साधारण पृष्ठभूमि की साधारण महिला द्रौपदी मुर्मू हैं राष्ट्रपति के रूप में। फिर हमारे पास सोनिया गांधी जैसी अति शालीनता वाली महिला हैं, जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता हैं।

ऐसे नेता हमारे राजनीतिक नेताओं के लिए आदर्श क्यों नहीं हैं, यह आश्चर्य की बात है। उच्च पदों पर आसीन होने के बावजूद वे सड़कछाप लफ्फाज और गुंडे की तरह व्यवहार क्यों करना पसंद करते हैं, यह बात और भी अधिक हैरान करने वाली है। यह आवश्यक है कि हम इस गिरते हुए असभ्य राजनीतिक व्यवहार की समस्या को गंभीरता से लें और अपने देश के लोकतंत्र के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में तुरंत आवश्यक कदम उठाएँ। जनवरी माह के अंत में महाकुम्भ प्रयागराज में एक भयानक दुर्घटना हुई जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। इस त्रासदी ने हमारे समक्ष आस्था, उसके प्रदर्शन और प्रसार से संबंधित कई प्रश्न खड़े किए है।   एक प्रश्न यह भी है की क्या आस्था को निहित स्वार्थ द्वारा राजनैतिक और आर्थिक लाभ का मुद्दा बनाने के बारे में कोई सामाजिक प्रतिबंध होना माननीय है। इन प्रश्नों पर गंभीरता से बात करने की आवश्यक है।

~प्रो प्रदीप माथुर

वक्फ की लड़ाई को बहुसंख्यक वर्ग का समर्थन

दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारती विकास गठबंधन (बीवीए) ने वक्फ संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध करने का संकल्प लिया है। हाल ही में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के साथ हुई बैठक में इसे वक्फ संपत्तियों के लिए गंभीर खतरा और सांप्रदायिक साजिश बताया गया। दोनों संगठनों ने इस विधेयक के खिलाफ हर संभव कदम उठाने पर सहमति जताई। मुंबई में आयोजित बैठक में दोनों मंचों ने भारत के संवैधानिक मूल्यों और अल्पसंख्यक अधिकारों पर हो रहे हमलों पर चर्चा की। उन्होंने सरकार पर हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ने और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। बैठक में एक कोर कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया, जो रणनीति तैयार कर एआईएमपीएलबी और बीवीए की मंजूरी के बाद इसे लागू करेगी।

पिछले साल, एआईएमपीएलबी ने समान नागरिक संहिता (UCC) के खतरे पर एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें विभिन्न समुदायों ने सामूहिक रूप से इसे खारिज किया। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर सरकार ने यह कदम उठाया, तो देशव्यापी आंदोलन होगा।

वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बीवीए और एआईएमपीएलबी ने एकजुट होकर इसका विरोध करने की प्रतिबद्धता जताई। बैठक के समापन पर एआईएमपीएलबी महासचिव मौलाना मोहम्मद फजलुर्रहीम मुजद्दिदी ने संविधान और हाशिए पर पड़े समुदायों की रक्षा का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि इस्लाम समानता और न्याय का समर्थन करता है और सभी भेदभाव को खारिज करता है। बैठक में दोनों संगठनों के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया और राष्ट्रीय चुनौतियों के खिलाफ एकजुटता बनाए रखने का वादा किया। **सैयद ख़लीक अहमद**

****

सरकारी कंपनी को नुकसान, प्राइवेट कंपनियों को लाभ

भारत सरकार द्वारा टेलीकॉम कंपनियों को ब्याज पर 50% और जुर्माने पर 100% छूट देने के प्रस्ताव से इन कंपनियों को लगभग ₹1 लाख करोड़ का फायदा होगा। वोडाफोन आइडिया को ₹52,000 करोड़, एयरटेल को ₹38,000 करोड़ और टाटा टेलीसर्विसेज को ₹14,000 करोड़ का लाभ होने की संभावना है। BSNL, जिसे 2000 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था, एक समय टेलीकॉम बाजार का शहंशाह था। लेकिन 2016 में रिलायंस Jio के बाजार में आने के बाद BSNL के बुरे दिन शुरू हो गए। Jio ने मुफ्त डेटा और कॉलिंग की पेशकश कर BSNL को भारी नुकसान पहुंचाया। साथ ही, 4G और 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में BSNL को बाहर रखा गया, जिससे वह 2G/3G तक सीमित रह गया।

BSNL के कमजोर होते ही निजी कंपनियों ने TRAI की मदद से महीने के 30 दिनों को 28 दिन का कर दिया और बिना रिचार्ज इनकमिंग सुविधा खत्म कर दी। रिचार्ज शुल्क भी दोगुने से अधिक हो गया, लेकिन सेवाएं गिरती रहीं। सरकार का यह कदम BSNL को कमजोर कर निजी कंपनियों को बढ़ावा देने का प्रतीक है। इससे जनता की जेब पर भारी असर पड़ा है, जबकि पारदर्शिता के अभाव में इस गोरखधंधे का खुलासा मुश्किल है। **श्याम सिंह रावत**

****

कुंभ ने भुलाया 22 जनवरी का “स्वतंत्र दिवस “

“असली आज़ादी” का दिन अभी पिछले दिनों आरएसएस के सरसंघचालक श्री मोहन भागवत ने घोषणा की थी कि भारत को 1000 साल की गुलामी से असली आज़ादी तो 22 जनवरी को मिली जब 1 साल पहले राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान हुआ। लोग समझ रहे थे कि इस साल बहुत धूमधाम से 22 जनवरी को असली आज़ादी की पहली सालगिरह मनाई जाएगी, लेकिन 22 जनवरी को तो कुछ भी नहीं हुआ। जो पत्रकार बड़े अरमानों से अयोध्या गए थे कि देखें 1000 साल के बाद मिलने वाली आज़ादी का जश्न कैसे मनाया जाता है, तो उनको बहुत बड़ी मायूसी हुई। उन्हें वहां पुजारियों ने कहा कि हमने तो अपने हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 11 दिन पहले ही इस पहली सालगिरह को मना लिया था। स्पष्ट है कि महाकुंभ के आयोजन में लगे होने के कारण मुख्यमंत्री से लेकर सभी बड़े बीजेपी नेता और धर्म के ठेकेदार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठान दिवस को भूल गए। - **प्रशांत गौतम**

****

बिशप की ट्रम्प को अपील: दया और करुणा की पुकार

जनवरी 21 , 2025 को वाशिंगटन नेशनल कैथेड्रल में उद्घाटन प्रार्थना सेवा के दौरान, बिशप मैरिएन एडगर बुड्डे ने राष्ट्रपति ट्रम्प से अप्रवासियों और LGBTQ समुदाय के प्रति दया और करुणा दिखाने का आग्रह किया। अपने उपदेश के दौरान, उन्होंने समलैंगिक, लेस्बियन और ट्रांसजेंडर बच्चों की सुरक्षा और आप्रवासियों की पीड़ा को संबोधित करते हुए कहा, "डरे हुए लोगों पर दया करें।"

मीडिया मैप फरवरी

यह अपील श्री ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के अगले दिन हुई, जब उन्होंने कई विवादास्पद कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। इन आदेशों में LGBTQ अधिकारों पर प्रतिबंध और आव्रजन कानूनों में कठोरता शामिल थी। बिशप ने कहा, "अधिकांश आप्रवासी अपराधी नहीं हैं। उन्हें दया और स्वागत मिलना चाहिए।" प्रार्थना सभा के दौरान, ट्रम्प ने बिशप के वक्तव्य को गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद उन्होंने ट्रुथ सोशल पर बिशप की आलोचना की, इसे "अनुचित" और "राजनीतिक" करार दिया।
बिशप बुड्डे ने अपनी टिप्पणियों का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति से सीधे बात करने का निर्णय लिया क्योंकि वह उन समुदायों के भय और दर्द को देख रही थीं, जो उनकी नीतियों से प्रभावित थे। उन्होंने कहा, "एक नेता के गुणों में दया होनी चाहिए।"
इस बीच, ट्रम्प प्रशासन ने नए आदेशों में "लिंग पहचान" को मान्यता न देने और "जैविक लिंग" पर आधारित परिभाषाओं को लागू करने का फैसला किया। आलोचकों ने इसे ट्रांसजेंडर अधिकारों पर हमला करार दिया। बिशप बुड्डे और अन्य धार्मिक नेताओं ने ट्रम्प की नीतियों पर सवाल उठाया है। उनका मानना है कि ऐसे निर्णय न केवल करुणा की कमी दर्शाते हैं, बल्कि विभाजन भी बढ़ाते हैं। **जगदीश गौतम**

****

बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न: कितना सच, कितना झूठ

हाल के वर्षों में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर कथित अत्याचारों और मंदिरों पर हमलों की खबरें भारतीय मीडिया में सुर्खियां बटोरती रही हैं। हालांकि, स्वतंत्र स्रोतों और बांग्लादेश सरकार के दावों के अनुसार, इनमें से कई रिपोर्टें भ्रामक या अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकती हैं।
स्वतंत्र तथ्य-जांच संगठनों के अनुसार, 12 अगस्त से 5 दिसंबर के बीच भारत के 49 मीडिया आउटलेट्स ने बांग्लादेश से जुड़ी 13 झूठी खबरें प्रकाशित कीं। इन खबरों में बांग्लादेश को एक "हिंदू-विरोधी" और "चरमपंथी" देश के रूप में पेश करने की कोशिश की गई। जबकि बांग्लादेश सरकार का कहना है कि हिंसा की घटनाओं का उद्देश्य किसी खास समुदाय को निशाना बनाना नहीं था, बल्कि यह राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता परिवर्तन से उपजी नाराजगी का परिणाम था।
शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद भारतीय मीडिया में चरमपंथी संगठनों के उभार और हिंदुओं पर हमले की खबरें सामने आईं। हालाँकि, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कार्यालय और जानकार सूत्रों ने इसे अतिरंजित बताते हुए कहा कि अधिकांश घटनाएँ स्थानीय विवादों तक सीमित थीं।
यह चिंताजनक है कि भारतीय मीडिया इन खबरों को बिना गहराई से जांचे व्यापक प्रचार देता है। बांग्लादेश ने भारतीय पत्रकारों को जमीनी हकीकत देखने का निमंत्रण दिया, लेकिन मीडिया कवरेज में कोई खास बदलाव नहीं हुआ।
भारत और बांग्लादेश के बीच मजबूत कूटनीतिक संबंध बनाए रखना जरूरी है। भ्रामक खबरें न केवल सांप्रदायिकता को भड़काती हैं बल्कि पड़ोसी देशों के रिश्तों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। **प्रदीप माथुर**

****

युद्धविराम गाजा के लिए एक नई सुबह

हमास और इज़राइल के बीच दशकों से चले आ रहे संघर्ष में 30 दिनों के संघर्ष विराम पर सहमति बनी है। गाजा में जारी हिंसा के बीच यह समझौता एक उम्मीद की किरण है, जिसे मिस्र, कतर, और अमेरिका ने सुगम बनाया। इस संघर्ष विराम में शत्रुता को रोकने और मानवीय संकट कम करने की योजना शामिल है। पहले चरण में, दोनों पक्ष 60 दिनों तक युद्ध विराम का पालन करेंगे। इसके बाद, हमास द्वारा बंधक बनाए गए 33 लोगों की रिहाई और इज़रायली जेलों में बंद 1,000 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई पर चर्चा होगी। साथ ही, गाजा में मानवीय राहत के लिए 600 से अधिक ट्रकों के जरिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाएगी।
दूसरे चरण में, राफा सीमा क्षेत्र से इज़रायली सैनिकों की वापसी की योजना है। हालांकि, इज़रायली सरकार के भीतर इसे लेकर विरोध है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू कट्टरपंथी गुटों के दबाव का सामना कर रहे हैं, जो इसे रियायत मानते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इज़रायल के बढ़ते अलगाव और सैनिकों की हताहत संख्या ने शांति वार्ता की आवश्यकता बढ़ा दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी सैन्य साधनों की सीमाओं को स्वीकारते हुए कूटनीतिक समाधान की वकालत की। यह संघर्ष विराम एक महत्वपूर्ण अवसर है, लेकिन स्थायी शांति के लिए सभी पक्षों से निरंतर प्रयास और विश्वास की जरूरत होगी। वैश्विक समुदाय उम्मीद कर रहा है कि यह कदम क्षेत्र में स्थिरता और शांति का मार्ग प्रशस्त करेगा। **डॉ सलीम खान**

****

आर्थिक मंदी और ट्रम्प का रुख वित्त मंत्री के लिए बड़ी चुनौतियां

प्रो शिवाजी सरकार

बजट 2025-26 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए एक कठिन चुनौती पेश करता है, क्योंकि उन्हें मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने, खपत को बढ़ावा देने, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने और धीमी अर्थव्यवस्था पर चिंताओं के बीच भारत के विकास को आगे बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से जूझना होगा।

वैश्विक मोर्चे पर, उन्हें नव-निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियों से संभावित आर्थिक बाधाओं को भी संबोधित करना होगा, जिसके परिणामस्वरूप पेट्रोल की कीमतें बढ़ सकती हैं और डॉलर मजबूत हो सकता है, जिससे भारत की आर्थिक जटिलताएँ बढ़ सकती हैं। भारतीय बजट 2025 घरेलू और वैश्विक गतिशीलता दोनों से आकार लेने वाली असंख्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए तैयार है। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में, इस बजट में उल्लिखित राजकोषीय नीतियों का सभी क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

भारत, कई अन्य देशों की तरह, कोविड-19 के कारण हुए आर्थिक व्यवधानों से उबरने की कोशिश कर रहा है। हालाँकि विकास दर में उछाल आ रहा है, लेकिन वैश्विक मांग में उतार-चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के बीच इस गति को बनाए रखना एक चुनौती बनी हुई है। इन दबावों में वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं भी शामिल हैं, जिनमें विकसित अर्थव्यवस्थाओं में संभावित मंदी भी शामिल है, जो भारत के निर्यात क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है और 2025 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के पूर्वानुमान को कम कर सकती है।

मुद्रास्फीति, विशेष रूप से खाद्य और ऊर्जा क्षेत्रों में, एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है, जिसके लिए व्यापक आर्थिक स्थिरता को प्रभावित किए बिना कमजोर आबादी का समर्थन करने के लिए संतुलित उपायों की आवश्यकता है। घरेलू स्तर पर, शहरी खपत, जो लंबे समय से विकास का एक विश्वसनीय चालक है, कमजोर हो गई है, और निजी निवेश कमज़ोर बना हुआ है। भारत की विकास दर दो साल के निचले स्तर 5.4 प्रतिशत पर आ गई है, 2024-25 के लिए वार्षिक विकास अनुमान 6.4 प्रतिशत है, जो 2023-24 में 8.2 प्रतिशत से तेज गिरावट है। फिर भी, भारतीय रिजर्व बैंक आशावादी बना हुआ है और जोर देकर कह रहा है कि देश के संरचनात्मक विकास के कारक बरकरार हैं। साथ ही, ग्रामीण

अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। भारतीय कृषि को बढ़ती जनसंख्या, सिकुड़ते भूमि संसाधन, जलवायु परिवर्तन, बढ़ती पोषण संबंधी मांग, श्रम की कमी, मशीनीकरण, मूल्य निर्धारण संबंधी दुविधाएं और पर्यावरण संबंधी चिंताओं सहित असंख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। समावेशी और सतत विकास प्राप्त करने के लिए इन कारकों को संतुलित करना महत्वपूर्ण होगा। सरकार नए बजट में कृषि व्यय को 15 प्रतिशत बढ़ाकर $20 बिलियन करने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आय को बढ़ावा देना और मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाना है। इस कोष में उच्च उपज वाली फसलों के विकास, भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने इस बजट में कई जटिल चुनौतियाँ हैं—मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, खपत को प्रोत्साहन, निजी निवेश में वृद्धि और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना करना। भारत की धीमी होती विकास दर और कृषि क्षेत्र की चुनौतियों के बीच, बजट से उम्मीदें अधिक हैं।

और दाल, तिलहन, सब्जी और डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दी जाएगी। हालाँकि, तत्काल प्रभाव अनिश्चित बना हुआ है, क्योंकि इनमें से कई पहलों के परिणाम देने में समय लगता है।

खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की रिपोर्ट, खाद्य सुरक्षा और पोषण का क्षेत्रीय अवलोकन 2023, से पता चला है कि 2021 में 74.1 प्रतिशत भारतीय स्वस्थ आहार का खर्च उठाने में असमर्थ थे, जो 2020 में 76.2 प्रतिशत से थोड़ा सुधरा है। हालाँकि, 2024-25 के बजट ने इन चुनौतियों का समाधान करने में सीमित प्रगति की है।

एनएसएसओ के नवीनतम घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण में ग्रामीण और शहरी आय में भारी असमानता पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें औसत ग्रामीण मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) शहरी एमपीसीई का सिर्फ 58 प्रतिशत है। जबकि हाल के वर्षों में ग्रामीण आय बढ़ाने के उद्देश्य से सुधार लागू किए गए हैं, प्रगति धीरे-धीरे हुई है।

पिछले पाँच वर्षों में, सरकार ने कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालयों को कुल बजट व्यय का औसतन 3 प्रतिशत आवंटित किया है, जो अधिक मजबूत समर्थन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। किसान अभी भी छोटी और खंडित भूमि जोत, मशीनीकरण को अपनाने में कमी, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। भारत में किसानों के सामने आने वाली कुछ प्रमुख समस्याओं में मिट्टी की उर्वरता में कमी और फसल बीमा योजनाओं तक अपर्याप्त पहुँच शामिल हैं।

कृषि वानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसी संबद्ध गतिविधियों के लिए

वैश्विक स्तर पर, अमेरिकी नीतियों के प्रभाव और ऊर्जा कीमतों में संभावित वृद्धि भी सरकार के लिए कठिनाइयाँ बढ़ा सकती हैं। ऐसे में, यह बजट आर्थिक संतुलन साधने, कृषि व ग्रामीण विकास को मजबूती देने और देश की वित्तीय नीतियों को नया आकार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

वित्त पोषण का विस्तार करना बहुत जरूरी है। मवेशी पालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन और झींगा पालन सहित छोटे पैमाने की मत्स्य पालन में निवेश ग्रामीण आय में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

वित्त मंत्री को विनिर्माण लागत कम रखने के लिए नई नीति के बारे में सोचना होगा ताकि मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहे। जीएसटी पर पुनर्विचार वांछनीय है। सरकार को संतुलन बनाने के लिए कुछ करना होगा। कर्ज का बोझ बहुत अधिक है। सड़कों सहित बुनियादी ढांचे के निवेश ने कॉर्पोरेट को लाभ पहुंचाया है, लेकिन टोल और इनपुट लागत में वृद्धि ने भारतीय खेती को मुश्किल बना दिया है। सड़क परियोजनाओं ने

50 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि का भी नुकसान किया है।

सरकार को नए ट्रम्पवाद से भी निपटना होगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार, पेट्रोल की कीमतों, वैकल्पिक ऊर्जा नीतियों में बदलाव, भारतीय निर्यात और रोजगार पर बहुत दबाव पड़ने की संभावना है। आईटी और एआई विकास भारतीय उद्यमों को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे रोजगार के मुद्दे और बढ़ रहे हैं। बैंक, हालांकि आरबीआई का कहना है कि वे अच्छी स्थिति में हैं, जमा राशि को पिघलाने की समस्या है। विनिर्माण और अन्य क्षेत्र व्यक्तियों की कम क्रय क्षमता से बाधित हैं।

रेलवे किराया और आवागमन लागत बढ़ रही है। क्या वित्त मंत्री इसे रोक पाएंगी? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हो सकती है, लेकिन अन्य क्षेत्रों की जरूरतों के साथ इसकी जरूरतों को संतुलित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। जबकि बजटीय प्रक्रिया महत्वपूर्ण जिज्ञासा पैदा करती है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण बदलाव आने की संभावना नहीं है। बजट के बाद, देश को अपनी आर्थिक दृष्टि को फिर से परिभाषित करना चाहिए, जो कम लागत वाली, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने पर केंद्रित हो।

****

कृषि क्षेत्र पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता

भारतीय कृषि वर्तमान में कई समस्याओं से जूझ रही है, जैसे कृषि उत्पादन की गिरती दर, बढ़ती लागत, स्थिर फसल उपज, और बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव। इसके परिणामस्वरूप, किसानों की आय में कमी आई है, जो खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका के लिए गंभीर चिंताओं का कारण बन रही है। इस स्थिति को कृषि विकास में मंदी के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि देश की कृषि उत्पादकता चीन, वियतनाम, और इंडोनेशिया जैसे देशों की तुलना में काफी कम है।

भारत की कृषि में कार्यरत श्रमिकों का जीवन स्तर भी बहुत निम्न है, उन्हें कम मजदूरी, उचित आवास की कमी और शिक्षा का अभाव है, जिससे कौशल में कमी देखी जाती है। किसानों के पास भूमि विकास के लिए पर्याप्त धन नहीं है, और सरकार का कृषि क्षेत्र में निवेश भी बहुत कम है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए बजट आवंटन बढ़ाने की कोशिश की है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इस क्षेत्र के लिए

> भारतीय कृषि आज गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है—गिरती उत्पादकता, बढ़ती लागत, और बाजार में उतार-चढ़ाव किसानों की आय पर गहरा प्रभाव डाल रहे हैं। जल संसाधनों की सीमितता और कृषि में निवेश की कमी इस स्थिति को और कठिन बना रही है। हालाँकि, सरकार द्वारा कृषि बजट बढ़ाने और किसान क्रेडिट योजनाओं का विस्तार करने जैसे प्रयास किए जा रहे हैं। क्या ये कदम भारतीय कृषि को पुनर्जीवित करने में सक्षम होंगे?

आवंटन बढ़ाकर लगभग ₹1.75 लाख करोड़ किए जाने का अनुमान है, साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कृषि ऋण की सीमा को भी बढ़ाने का प्रस्ताव है।

भारत की कृषि संस्थाएँ और बुनियादी ढांचा अविकसित हैं, और कृषि उद्यमियों के विकास में गरीबी, भूमि संसाधनों का असमान वितरण और अन्य सामाजिक समस्याएं बाधक बनी हुई हैं। लगभग 70% भारतीय गरीबी से जूझ रहे लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जो कृषि पर निर्भर हैं। भारत की खाद्य सुरक्षा अनाज के उत्पादन पर निर्भर है, साथ ही बढ़ती आबादी की मांगों को पूरा करने के लिए फलों, सब्जियों और दूध का उत्पादन भी बढ़ाना आवश्यक है।

भारत को वैश्विक कृषि शक्ति माना जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा दूध, दालों, और मसालों का उत्पादक है और इसके पास सबसे बड़ा मवेशी झुंड भी है। इसके अलावा, भारत गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, मछली पालन, भेड़ और बकरी के मांस, फल, सब्जियाँ और चाय के उत्पादन में भी अग्रणी है। देश में लगभग 195 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है, जिसमें 63% भूमि वर्षा आधारित और 37% सिंचित है।

हालाँकि, भारतीय कृषि को कई गंभीर चुनौतियों का सामना है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कुछ प्रमुख कदम उठाए जाने चाहिए। इनमें पैदावार बढ़ाने, उच्च मूल्य वाली फसलों में विविधता लाने और विपणन लागत को कम करने के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास शामिल है। इसके अलावा, जल संसाधनों की सीमितता और बढ़ती औद्योगिक और शहरी जरूरतों के कारण, जल प्रबंधन को बेहतर बनाने की आवश्यकता है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए सामाजिक समावेशी रणनीतियाँ अपनाई जानी चाहिए, जिसमें गैर-कृषि रोजगार को भी बढ़ावा दिया जाए। गरीबों, भूमिहीनों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को लाभ पहुंचाने के प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही, क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि भारत के अधिकांश गरीब लोग वर्षा आधारित क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ कृषि की स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण है।

भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध, दाल, और मसालों का उत्पादक है, आज कृषि क्षेत्र में स्थिरता की चुनौती से जूझ रहा है। अनियमित वर्षा, भूमि संसाधनों का असमान वितरण और ग्रामीण गरीबी कृषि विकास में बाधा बने हुए हैं। क्या हरित क्रांति जैसी कोई नई पहल कृषि क्षेत्र में फिर से क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है? इस लेख में पढ़ें कि कैसे भारतीय कृषि को एक मजबूत और टिकाऊ प्रणाली में बदला जा सकता है।

कृषि क्षेत्र की मंदी और धीमी वृद्धि के बावजूद, 1970 के दशक की हरित क्रांति के बाद खाद्यान्न उत्पादन में हुई तीव्र वृद्धि ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने में मदद की थी। हालांकि, 1990 और 2000 के दशक में कृषि विकास धीमा हो गया, और अनाज की पैदावार में वृद्धि बहुत कम हो गई है। इस स्थिति को देखते हुए, नीति निर्माताओं को इस क्षेत्र में मौजूदा नीतियों और संस्थागत व्यवस्थाओं की समीक्षा करने और कृषि क्षेत्र को अधिक उत्पादक और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नीतिगत कदम उठाने की आवश्यकता है।

समाप्त करने के लिए, भारतीय कृषि को मजबूती देने के लिए एक ठोस रणनीति की आवश्यकता है, जो खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन और विकास की दिशा में प्रभावी कदम उठाए।

****

भारत को एक नई अर्थव्यवस्था की जरूरत है

भारतीय लोग केंद्रीय बजट पेश होने के बाद किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का विश्वास करों पर कर और मुद्रास्फीति के माध्यम से मुक्त-प्रवाह शोषण को बढ़ावा दे रहा है, जिससे विकास बाधित हो रहा है।

भारत को स्वतंत्रता के बाद के पहले दशक के आर्थिक दृष्टिकोण से सीखना चाहिए, जो कई आकांक्षाओं से भरा हुआ था। कुछ आकांक्षाएं पंचवर्षीय योजनाओं, बिजली परियोजनाओं, नई सड़कों, नए उद्योगों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, कृषि और अन्य संस्थानों और विशाल सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) के माध्यम से पूरी हुईं। यह प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में नेताओं की दूरदर्शिता का परिणाम था।

इसके साथ ही कई क्षेत्रों के लिए अधिकार-आधारित श्रम कानून सुधार भी किए गए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सरकारी क्षेत्र उभरे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इनमें से अधिकांश सुधार निरस्त कर दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना है कि संस्थापकों के दूरदर्शी दृष्टिकोण के कारण देश की आय में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पहले 11-12 प्रतिशत की वृद्धि की परिकल्पना की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, राष्ट्रीय आय में 11-12 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद थी; योजना व्यय में कमी के बावजूद वास्तविक वृद्धि 18 प्रतिशत से अधिक

थी। आईएमएफ ने कहा कि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता की स्थितियों में पहली योजना की सफलता ने दूसरी योजना को तैयार करने में अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य और अधिक साहसिक दृष्टिकोण को प्रेरित किया।

इससे एक बुनियादी मुद्दा उठता है कि 1991 के तथाकथित उदारीकरण और लाइसेंस-परमिट राज के अंत के बाद से भारत की प्रगति सुस्त क्यों रही है या यह केवल कॉर्पोरेट वर्ग की ओर झुकी हुई क्यों है, जिससे आम जनता की उपेक्षा हुई। "रियायतें और प्रोत्साहन" के खत्म होने के साथ, वास्तविक रूप से निवेश मूंगफली जितना या काफी हद तक सरकारी जिम्मेदारी बन गया था। आम आदमी सिर्फ़ एक खूंटी था, अगर मोहरा नहीं। उद्योगों ने अपने मुनाफे से ज्यादा

> भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्त विकास दर, निवेश में गिरावट और बढ़ती बेरोजगारी जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। 2024-25 के बजट से उम्मीदें थीं, लेकिन क्या यह आर्थिक अस्थिरता को दूर कर पाएगा? क्या सरकार की नीतियां आम जनता और किसानों के हित में हैं, या केवल कॉर्पोरेट जगत को लाभ पहुंचा रही हैं? जानिए इस विश्लेषण में।

निवेश नहीं किया। उन्होंने बैंकों के खजाने खाली कर दिए और मजबूत सिस्टम को अभूतपूर्व गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के रसातल में ले गए। इसका मतलब था कि उन्होंने ऋण नहीं चुकाया। कई लोग देश छोड़कर भाग गए और अन्य ने माफ़ी मांगना पसंद किया।

बजट में चिंता तो जताई गई, लेकिन कभी उन्हें दंडित नहीं किया गया। लोगों को नौकरियां जाने का सामना करना पड़ा, जिसे कॉरपोरेट ने नहीं बनाया या फिर सार्वजनिक उपक्रमों को बंद करके उन्हें थोपा, जिससे बिना किसी जिम्मेदारी के एकाधिकार स्थापित हुआ।

हाल ही में एक नई परिघटना विकसित हुई है। ढेरों फंड रखने वाली कई बड़ी कंपनियां निवेश से कतराती हैं। उनकी आशंका निराधार नहीं है। निजी क्षेत्र के मालिकों का मानना है कि उन्हें डर है कि अगर वे निवेश करेंगे और विकास करेंगे, तो उनके बीच के कुछ शिकारी उन्हें विलय के लिए मजबूर कर देंगे या उनकी फलती-फूलती इकाइयों पर कब्ज़ा कर लेंगे। बजट, जो अब इसे रोकने का एकमात्र साधन है, विनाशकारी स्थिति से निपटने की क्षमता नहीं रखता है। यह विनाशकारी है क्योंकि यह उस देश के निवेश और प्रगति को धीमा कर देता है, जिसे उन सभी क्षेत्रों में सरकारी अनुदानों से सब्सिडी दी जा रही है, जहां कॉर्पोरेट विफल रहे हैं - रोजगार से लेकर कल्याण तक - मनरेगा से लेकर मुफ्त खाद्यान्न, डीएपी-प्रकार के उर्वरकों के लिए निरंतर सब्सिडी, जबकि किसान लाभकारी कीमतों और बाजार प्रणाली के लिए रो रहे हैं।

यहां तक कि विदेशी निवेश में भी गिरावट आ रही है और विदेशी

> भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्त विकास दर, निवेश में गिरावट और बढ़ती बेरोजगारी जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। 2024-25 के बजट से उम्मीदें थीं, लेकिन क्या यह आर्थिक अस्थिरता को दूर कर पाएगा? क्या सरकार की नीतियां आम जनता और किसानों के हित में हैं, या केवल कॉर्पोरेट जगत को लाभ पहुंचा रही हैं? जानिए इस विश्लेषण में।

पोर्टफोलियो निवेश में भी तेजी से गिरावट देखी जा रही है। 2023 में शानदार प्रदर्शन के बाद, विदेशी निवेशकों ने 2024 में भारतीय इक्विटी में अपने निवेश को काफी हद तक कम कर दिया, जिसमें शुद्ध प्रवाह 5,000 करोड़ रुपये से अधिक था। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) प्रवाह 2024 में 99 प्रतिशत घटकर 2026 करोड़ रुपये रह गया, जो 2023 में 1.71 लाख करोड़ रुपये था। अकेले अक्टूबर 2024 में एफपीआई ने भारतीय इक्विटी से 22,194 करोड़ रुपये निकाले, जो कमजोर आय सीजन की उम्मीदों से प्रेरित था।

इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत की वृद्धि दर दो साल के निचले स्तर 5.4 प्रतिशत पर आ गई है और

वार्षिक 2024-25 की वृद्धि दर को लगातार 7 प्रतिशत से संशोधित कर 6.6, 6.5 और अब उद्योग निकाय फिक्की ने 6.4 प्रतिशत का अनुमान लगाया है। यह उन लोगों के लिए बहुत कुछ कहता है जो उल्लेखनीय योजना प्रक्रिया और भारत के शुरुआती विकास आंकड़ों की आलोचना करते रहे हैं।

देश को अपनी समीक्षा और नियोजन प्रक्रिया को मजबूत करने की आवश्यकता है। विकास वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है, जो कि अधिक से अधिक वित्त प्रबंधक है, आर्थिक नहीं। इस स्थिति पर चर्चा करने की चिंता है। भारत को मनमोहनोमिक्स को त्यागकर अपने अर्थशास्त्र को फिर से तैयार करने की आवश्यकता है, जिसने केवल इस विनाशकारी स्थिति को जन्म दिया है।

यह आसान रास्ता नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। सभी प्रमुखों को एक साथ मिलकर देश को समृद्धि की ओर ले जाना होगा, जिसकी शुरुआत नए वित्तीय वर्ष से होगी और तब तक जारी रहना होगा जब तक कि यह मुगल काल और उससे पहले की तरह वैश्विक नेता न बन जाए। अभी भी कुछ चिंगारियाँ हैं और अगर सही दिशा में काम किया जाए, तो भारत को दुनिया की सबसे जीवंत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने से कोई नहीं रोक सकता।

मोहम्मद नौशाद खान लिखते है

प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार ने भारत की जीडीपी गणना के बारे में गंभीर चिंताओं को उजागर करते हुए कहा: "2016 में नोटबंदी के बाद, जीडीपी में 5% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन वास्तव में, अगर अनौपचारिक क्षेत्र को सही तरीके से शामिल किया जाए तो यह 1-2% से अधिक नहीं हो सकती है। अनौपचारिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का लगभग 94% हिस्सा है, लेकिन आधिकारिक गणनाओं में इसे काफी हद तक नजरअंदाज किया जाता है।

> प्रोफेसर अरुण कुमार का कहना है कि आधिकारिक जीडीपी आंकड़े अनौपचारिक क्षेत्र की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाते, जिससे आर्थिक विकास की गलत तस्वीर बनती है। उन्होंने जीएसटी में सुधार, सामाजिक क्षेत्र में निवेश और कर प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। क्या भारत को आर्थिक नीतियों में बड़ा बदलाव करना चाहिए? पढ़ें इस खास विश्लेषण में।

इस पर ध्यान देने के लिए रोजगार बढ़ाने और असमानताओं को कम करने के लिए कृषि और छोटे व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।"

प्रोफेसर कुमार ने अनौपचारिक क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ढांचे में सुधार की भी वकालत की। उन्होंने जोर दिया: "इस क्षेत्र को जीएसटी के तहत इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है, जिससे औपचारिक व्यवसायों को असंगत लाभ मिलता है। अनौपचारिक क्षेत्र को शामिल करने के लिए जीएसटी में सुधार समानता के लिए आवश्यक है।"

सामाजिक क्षेत्र में प्रोफेसर कुमार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स में सुधार, आयकर को सरल बनाने तथा संसाधन जुटाने के लिए अनौपचारिक क्षेत्र से कर वसूलने की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा, उन्होंने आय असमानताओं को दूर करने के लिए संपत्ति, उत्तराधिकार और उपहार कर लगाने का आह्वान किया तथा मलेशिया के उदाहरणों का उल्लेख किया, जिसने आर्थिक व्यवधानों को रोकने के लिए पूंजी नियंत्रण को सफलतापूर्वक प्रबंधित किया।

उन्होंने निष्कर्ष निकाला: "ऐसे उपायों को लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है, जिसे सामाजिक आंदोलनों और श्रमिक वर्ग, महिलाओं और हाशिए के समूहों को शामिल करते हुए सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से जुटाया जा सकता है।"

****

लेखक मीडिया मैप के सहयोगी सम्पादक है।

भारतीय राजनीति के विलक्षण पुरुष अरविंद केजरीवाल

प्रो प्रदीप माथुर

अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति की एक अनबूझ पहेली हैं। एक बड़े सरकारी अधिकारी होने के साथ-साथ वह सूचना अधिकार की मुहिम के साथ जुड़े, फिर वह अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की सीढ़ियों चढ़कर राजनीति के क्षेत्र में आए। यकायक चुनाव के मैदान में उतरकर उन्हें आशातीत सफलता मिली तथा वह देश के शीर्ष नेताओं में शुमार हो गए। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को समझ में ही नहीं आया कि उनका राजनीति में अहम और विकास कैसे और किन कारणों से हुआ?

> अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने समर्थकों से वादा किया कि वे न तो रिश्वत लेंगे और न ही देंगे। हालांकि, यह जल्द ही स्पष्ट हो गया कि उनकी परिभाषा में भ्रष्टाचार केवल नकद लेन-देन तक सीमित थी

सत्ता में आने से पहले केजरीवाल के पास दलगत राजनीति का कोई अनुभव न था, पर यह बात माननी पड़ेगी कि उनके पास राजनीति की बारीकियों को समझने की बुद्धि ज़रूर थी। वह उस स्थिति का भली-भाँति आकलन कर पाए, जिसमें जनसमर्थन के अभाव में मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की कांग्रेस कमजोर हो गई थी और मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तेजी से राजनीति का वह खाली स्थान भरने का प्रयास कर रही थी।

राजनीति में खाली पड़े मैदान को समझ पाने की इसी क्षमता के चलते केजरीवाल अपनी पार्टी को पंजाब के चुनाव में अभूतपूर्व विजय दिलाने में सफल रहे। गुजरात और हरियाणा में, जहाँ भाजपा और कांग्रेस की अच्छी पकड़ थी, वह बिल्कुल भी सफल नहीं हुए। केजरीवाल यह भी जानते हैं कि भारतीय राजनीति में आपको हमेशा नैतिकता और मूल्यों की बात करनी चाहिए। उनकी नैतिकता और ईमानदारी उसी तरह संदेह के घेरे में है, जैसे अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं की, पर वह मतदाताओं के मन में एक अच्छी छवि बनाकर चुनावी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते आए हैं।

राजनीति में तेजी से बढ़ते कद के कारण जहाँ केजरीवाल स्वयं महत्वाकांक्षा के शिकार हो गए,

वहीं दूसरी तरफ उनके राजनीतिक विरोधी भी उनके खिलाफ लामबंद हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेतृत्व को वर्ष 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद दिल्ली विधानसभा का वर्ष 2015 और 2020 में हारना शूल की तरह चुभा। इसके कारण प्रधानमंत्री मोदी और केजरीवाल के बीच अहम का टकराव हुआ तथा भाजपा के लिए केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, राहुल गांधी तथा कांग्रेस से भी बड़े शत्रु हो गए।

आम आदमी पार्टी ने राजनीति में पारदर्शिता, वीआईपी संस्कृति का त्याग और चुनावी टिकट केवल जमीनी कार्यकर्ताओं को देने का वादा किया। हालांकि, चुनावी टिकट वितरण में पारदर्शिता से भटकते हुए पार्टी ने कुछ विवादास्पद फैसले लिए।

अक्सर यह भी कहा जाता है कि केजरीवाल हृदय से हिंदुत्ववादी हैं और उन्हें आरएसएस का गुप्त समर्थन प्राप्त है। यह कहने वालों का मानना है कि केजरीवाल का विरोध मोदी से है, ना कि भगवा ब्रिगेड से और उनके असली राजनीतिक शत्रु कांग्रेस तथा वामपंथ की तरह झुकाव रखने वाले अन्य धार्मिक निरपेक्ष राजनीतिक दल हैं। अगर हम विगत गुजरात और हरियाणा विधानसभा के चुनाव और पहले वर्ष के दिल्ली के लोकसभा चुनाव को देखें, तो यह बात काफी हद तक ठीक लगती है।

अति महत्वाकांक्षा के साथ-साथ केजरीवाल की दो और समस्याएँ भी हैं। वह विचारधारा शून्य राजनीति कर रहे हैं और यह नहीं समझते हैं कि ऐसी राजनीति का जीवन लंबा नहीं हो सकता। अगर वह समझते हैं कि हिंदुत्व की ओर उनका झुकाव आम आदमी पार्टी को भाजपा की तुलना में आरएसएस के अधिक करीब ला पाएगा, तो यह उनकी भूल है।

उनकी दूसरी समस्या यह है कि अपने को आम आदमी पार्टी का नेता कहने और दिल्ली की गरीब जनता का मानसपुत्र बताने के बावजूद उनकी मनोवृत्ति सामंतवादी है, जो हमारी नौकरशाही का सामान्य लक्षण है। इसी कारण उन तमाम लोगों को

सूचना का अधिकार (आरटीआई) आंदोलन ने सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आक्रोश को जन्म दिया, जो 2011 में अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में तेज हुआ। अन्ना हजारे का लोकपाल विधेयक की मांग का आंदोलन मीडिया और जनता का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहा।

पार्टी के बाहर कर दिया गया, जिनका व्यक्तित्व उनसे बड़ा और सामाजिक भाव वाला था। यदि वे सब लोग आम आदमी पार्टी में होते, तो वास्तव में आम आदमी पार्टी एक अच्छे और शक्तिशाली दल के रूप में भाजपा और कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बन सकती थी। लेकिन असुरक्षा के भाव में अपने को सबसे ऊपर रखने की प्रवृत्ति के कारण केजरीवाल ने इसकी संभावना समाप्त कर दी। वह भूल गए कि भारतीय राजनीति में ऊपर उठने का वास्तविक मार्ग त्याग है, ना कि पद प्राप्ति।

****

लेखक वरिष्ठ पत्रकार, मीडिया गुरु एवं मीडिया मैप के संपादक हैं।

चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठते प्रश्न

डॉ. मुजफ्फर हुसैन ग़ज़ाली

भारत निर्वाचन आयोग, जो कभी निष्पक्षता का पर्याय था, अब पक्षपात और राजनीतिक हस्तक्षेप का शिकार हो चुका है। यह स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब स्वतंत्र चुनाव कराने की इस संस्था पर धांधली और पक्षपात के आरोप लगते हैं।

संसदीय लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं और चुनावों का विशेष महत्व है। संवैधानिक संस्थाएं नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने का काम करती हैं तथा चुनाव आयोग निष्पक्ष एवं न्यायसंगत चुनाव कराता है। जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि ये संस्थाएं राजनीतिक शक्ति से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करें। उनकी लापरवाही शासकों को अधिनायकवादी बना सकती है और लोकतंत्र को तानाशाही में बदल सकती है। हाल के वर्षों में देश जिस दिशा में तेजी से बढ़ रहा है, उससे कमोबेश सभी परिचित हैं।

इस समय हमें दिल्ली चुनाव के संदर्भ में चुनाव आयोग की भूमिका पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चुनाव कराने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसी पर है। आयोग चुनावों में रेफरी का काम करता है। यह जितना अधिक निष्पक्ष और स्वतंत्र होगा, चुनावी राजनीति में जनता का विश्वास उतना ही अधिक बढ़ेगा। पिछले दस वर्षों में उस पर जितने आरोप लगे और उंगलियां उठीं, उसने कभी कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं दिया। जनता के बीच चुनाव आयोग के बारे में फैली भ्रांतियों को दूर करने के बजाय दिल्ली चुनाव अधिकारी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भाजपा के ट्वीट को रीट्वीट कर दिया। यह पोस्ट भाजपा नेताओं की चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक के बारे में थी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने इसका स्क्रीनशॉट साझा करते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया।

> भारत निर्वाचन आयोग, जो पहले निष्पक्षता का प्रतीक था, अब पक्षपात और राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोपों का शिकार हो चुका है। खासतौर पर दिल्ली चुनाव में, जब चुनाव आयोग ने भाजपा के ट्वीट को रीट्वीट किया, तो आम आदमी पार्टी और विपक्ष ने इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए।

कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के पक्षपातपूर्ण रवैये की कड़ी आलोचना की थी। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन चुनावों में चुनाव आयोग ने खुलेआम पक्षपात दिखाया है। वहां माहौल कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन नतीजे अप्रत्याशित रूप से भाजपा और एनडीए के पक्ष में आए। 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि उनकी बातें सही साबित होने लगीं। संजय सिंह ने अपने ट्वीट में तंज कसते हुए लिखा कि चुनाव अधिकारी औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल होंगे और उसके लिए प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार नई दिल्ली के चुनाव अधिकारी ने गुपचुप तौर पर भाजपा के ट्वीट को रीट्वीट करना शुरू कर दिया है।

देश पिछले कुछ समय से देख रहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में विपक्ष को कमजोर करने की जो चालें चली जा रही हैं, उसमें चुनाव आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसे एक जेबी संस्था बनाने की कोशिश की गई है जिसका काम सरकार के निर्देशों का पालन करना है। सभी चुनाव कार्यक्रम सत्ताधारी दल की सुविधा के अनुसार तय किए जाते हैं। चुनाव की तारीखें घोषित होने के बाद बदल दी जाती हैं। चुनाव आयोग द्वारा घोषणा करने से पहले ही सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं को पता होता है कि कौन सी तारीखों की घोषणा होने वाली है।

भाजपा सरकार ने चुनाव आयोग को काफी हद तक कमजोर कर दिया है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मिलकर करते थे। लेकिन पिछली सरकार ने एक कानून लाकर मुख्य न्यायाधीश को इस समिति से हटा दिया। इस प्रकार, सरकार को चुनाव

आयुक्त की नियुक्ति पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो गया और विपक्ष की इसमें कोई भूमिका नहीं रही। विपक्ष ने कई राज्यों और पिछले लोकसभा चुनावों में भाजपा और चुनाव आयोग के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया था। हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ हुए उपचुनावों में भी यह बात सामने आई कि सुबह में जो रुझान थे, वे डेढ़ घंटे के अंदर ही बदल गए। दोपहर तक भाजपा जीत गई और सारी अटकलें विफल हो गईं। यह खेल कई राज्यों में खेला जाता रहा है।

कई निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर संदिग्ध गतिविधियां देखी गईं या उनमें छेड़छाड़ के स्पष्ट संकेत मिले। उल्लेखनीय है कि कई मशीनें लंबे समय तक उपयोग के बाद भी गिनती के समय 99% तक चार्ज पाई गईं, जो यह दर्शाता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। चुनाव आयोग ने न केवल इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि नोट बांटने, धार्मिक ध्रुवीकरण में शामिल होने तथा खुलेआम सांप्रदायिक बयानबाजी करने वाले भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के विरुद्ध भी कोई कार्रवाई नहीं की। चुनाव आयोग ने पुलिस अधिकारियों द्वारा लोगों को मतदान करने से रोकने और मतगणना में धांधली के मामलों पर भी चुप्पी साध ली।

चंडीगढ़ के मेयर का मामला तो अदालत के हस्तक्षेप से सुलझ गया, लेकिन कई क्षेत्रों में दो बार गिनती में चुनाव जीते हुए उम्मीदवार को हराने के लिए बल प्रयोग किया गया, फिर भी आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा हार सकती थी, वहां के एसपी और डीएम को बदला गया और गृह मंत्रालय द्वारा मतगणना से पहले प्रशासन को निर्देश दिए गए। लेकिन विपक्ष को मामूली चूक के लिए भी नोटिस जारी कर दिया जाता है।

इसलिए विपक्ष, बुद्धिजीवी और स्वयंसेवी संगठन चाहते हैं कि मतदान मतपत्रों के माध्यम से कराया जाए। लेकिन सरकार और चुनाव आयोग इस पर विचार करने को तैयार नहीं हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कई विपक्षी दल चुनाव आयोग से मिलकर इस मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहते थे और डेमो के जरिए यह भी दिखाना चाहते थे कि मशीनों को हैक किया जा सकता है, लेकिन चुनाव आयुक्त ने उन्हें समय नहीं दिया। अमेरिकी

> ईवीएम के प्रति लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, और विपक्ष का कहना है कि मशीनें हैक की जा सकती हैं। चुनाव आयोग ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इसके अलावा, नए मतदान प्रणाली और संशोधित आंकड़ों ने चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के संदेह को और बढ़ा दिया है, जिससे लोकतंत्र पर खतरे के निशान उभर रहे हैं।

टेक्नोक्रेट एलन मस्क ने भी पुष्टि की है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को हैक किया जा सकता है। उन्होंने डाक द्वारा एकत्रित वोटों में भी अनियमितताओं की बात कही है। दुनिया भर के कई देशों ने ईवीएम के बजाय मतपत्रों से मतदान कराना शुरू कर दिया है। हमारे पड़ोसी देशों में भी बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, लेकिन भारत इसे छोड़ने को तैयार नहीं है।

चुनाव आयोग ने हाल ही में मतों की गिनती के लिए एक नई प्रणाली अपनाई है, जिसके तहत मतदान समाप्त होने के कई घंटे बाद संशोधित आंकड़े जारी किए जाते हैं। दोनों में मामूली अंतर नहीं, बल्कि 5-7 प्रतिशत का अंतर होता है, जो किसी भी नतीजे को बदलने के लिए पर्याप्त है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद मात्र चार-पांच महीनों में मतदाताओं की संख्या में 47 लाख की वृद्धि हुई, जिससे विपक्ष के मत बढ़ाने और मतदाता सूचियों से नाम हटाने के संदेह को बल मिलता है।

दिल्ली चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में योगी आदित्यनाथ एक दर्जन रैलियां करेंगे। 2020 के चुनावों में भी नफ़रत का एजेंडा खुलेआम चलाया गया था। सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग इसे रोकेगा? और विपक्ष इसका मुकाबला कैसे करेगा? पूर्व सांसद उदित राज का कहना है कि भले ही भाजपा हिंदू-मुसलमानों को बांटती हो, लेकिन कांग्रेस का उद्देश्य लोगों को बांटकर वोट मांगना नहीं है।

अक्सर चुनाव से पहले या नतीजे आने के बाद ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव के बीच में यह मुद्दा उठाया कि चुनाव आयोग भाजपा की मदद कर रहा है। दिल्ली चुनाव कार्यालय की ओर से भाजपा के ट्वीट को रीपोस्ट करने की घटना ने इसकी पुष्टि कर दी। सवाल यह है कि विपक्ष और जनता चुनाव आयोग के खिलाफ जन आंदोलन क्यों नहीं चलाते? विपक्ष को जनता को विश्वास में लेकर कठोर निर्णय लेने होंगे। तभी चुनाव आयोग की निष्पक्षता सुनिश्चित हो सकेगी और लोकतंत्र बचा रहेगा।

****

लेखक : पत्रकार एवं स्तंभकार तथा यू एन एन के संपादक है।

कुंभ त्रासदी

आस्था के पर्व को राजनैतिक लाभ, और व्यवसाय बनाने का परिणाम

प्रशांत गौतम

महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज में हुए हादसे ने योगी सरकार की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर स्नान के लिए पहुंचे थे, और उसी दौरान एक भयावह भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। हालांकि, सरकारी आंकड़े कुछ कम थे, लेकिन वास्तविक आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं। यह घटना प्रशासन की नाकामी को उजागर करती है, खासतौर पर तब जब सुरक्षा इंतजामों को लेकर बड़े-बड़े दावे किए गए थे।

सरकार ने शुरुआत में दावा किया था कि स्नान घाटों के आसपास सख्त सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें सीसीटीवी, ड्रोन और एआई उपकरण लगाए गए थे। लेकिन हादसे के समय यह सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से विफल साबित हुई। प्रशासन ने लाखों श्रद्धालुओं के आने के लिए कोई ठोस योजना तैयार नहीं की, और सुरक्षा की जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं लिया। इस स्थिति में जब भगदड़ मची, तो प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। एक महिला पुलिसकर्मी ने बार-बार कंट्रोल रूम में स्थिति की गंभीरता बताई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई कदम नहीं उठाया। डीआईजी वैभव कृष्णा का बयान कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं दी गई, प्रशासन की लापरवाही को और स्पष्ट करता है।

> महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज में हुई भगदड़ ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी। लाखों श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किए गए बड़े दावे पूरी तरह विफल साबित हुए, और हादसे के बाद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

वीआईपी संस्कृति की वापसी भी प्रशासन की विफलता का उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 में वीआईपी संस्कृति खत्म करने का वादा किया था, और योगी आदित्यनाथ ने भी 2024 में ऐसा करने का ऐलान किया था, लेकिन प्रयागराज महाकुंभ में वीआईपी पासों का वितरण हुआ, जिससे सामान्य श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। यह स्थिति प्रशासन के खोखले दावों को उजागर करती है। मीडिया ने भी इस पर कोई सवाल नहीं उठाए, और यह स्थिति और भी चिंता का कारण बनती है।

कुंभ मेला अब केवल धार्मिक आयोजन नहीं रह गया है, बल्कि यह एक बड़े व्यवसाय और राजस्व का स्रोत बन चुका है। तंबू का किराया 40,000 रुपये तक पहुंच गया है, और चाय की दुकान के लिए 16 लाख रुपये तक की बोली लगाई गई। सरकार का दावा है कि 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन से 25,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा, लेकिन यह दावे वास्तविकता से दूर हैं। इतने बड़े आयोजन के लिए आवश्यक संसाधन और लॉजिस्टिक्स की व्यवस्थाएं पूरी तरह से असंभाव्य हैं।

कुंभ मेला अब राजनीतिकरण और व्यवसायीकरण का शिकार हो चुका है। कुंभ का आयोजन पहले जहां आस्था से जुड़ा हुआ था, अब यह एक बड़े राजनीतिक और आर्थिक आयोजन में बदल गया है। वीआईपी पासों के कारण सामान्य श्रद्धालुओं को कई किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि वीआईपी लोग आराम से पहुंच

गए। इसके अलावा, प्रशासनिक व्यवस्थाओं की कमी भी स्पष्ट रूप से देखी गई। ट्रैफिक, पार्किंग, और सुरक्षा की व्यवस्थाएं अत्यधिक असंतोषजनक थीं, और इन खामियों ने कुंभ मेले की छवि को धूमिल किया है।

इसके अलावा, कुंभ मेला भारतीय समाज की विविधता, सहिष्णुता और संवाद का प्रतीक भी है। यह एक ऐसा मंच हो सकता है जहां विभिन्न धर्मों के लोग एकत्रित हो और संवाद स्थापित करें, लेकिन अब यह राजनीतिक और व्यावसायिक एजेंडों का हिस्सा बन चुका है। नेताओं का प्रचार और राजनीतिक प्रभाव ने इस मेले के धार्मिक उद्देश्य को कमजोर कर दिया है। सरकार द्वारा किए गए दावे और राजनीतिक प्रभाव ने इसे एक राजनीतिक मंच बना दिया है।

> महाकुंभ अब एक बड़े व्यवसाय का रूप ले चुका है। तंबू का किराया 40,000 रुपये तक पहुंचने और चाय की दुकान के लिए लाखों रुपये की बोली लगने से यह आयोजन धार्मिक आस्था से ज्यादा एक व्यावसायिक आयोजन बन गया है।

कुंभ मेला प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है। यातायात प्रबंधन, पार्किंग, और सुरक्षा की समस्याएं असंतोषजनक रहीं। इसके अलावा, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करना भी एक राजनीतिक कदम प्रतीत होता है, जो वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास लगता है। यह नामकरण विवादास्पद है और इससे कोई ठोस परिणाम नहीं निकलता।

कुंभ मेला संवाद और समन्वय का महत्वपूर्ण मंच हो सकता है। यह एकता, सहिष्णुता और समाजिक समन्वय को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन अब यह राजनीति और व्यवसाय का केंद्र बन चुका है। सरकार को चाहिए कि इसे सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा न बनाए, बल्कि इसे एक सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बनाए।

अंत में, कुंभ मेला भारतीय संस्कृति, आस्था और सामाजिक समन्वय का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि विभिन्न धर्मों, जातियों और समुदायों के बीच संवाद और एकता आवश्यक है। कुंभ का वास्तविक संदेश यही है – विविधता में एकता। यह भारत की सबसे बड़ी ताकत है, और हमें इसे सहेजना चाहिए।

हालांकि, आजकल इस पवित्र आयोजन का राजनीतिकरण और व्यवसायीकरण हो रहा है। सरकार द्वारा साढ़े तीन करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने के दावे ने विवाद पैदा किया है। यह आंकड़ा अव्यावहारिक और असंभव लगता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एक ही दिन में कुंभ क्षेत्र में समायोजित करना संभव नहीं है। अंत में, यह कहा जा सकता है कि कुंभ मेला भारतीय संस्कृति और समाज का प्रतीक है। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एकता, संवाद और विचारों का संगम है। यदि हम इसके वास्तविक उद्देश्य को समझें और इसे धार्मिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से ऊपर उठाकर देखें, तो यह मेला समाज में एकता, सामंजस्य और मानवता का संदेश दे सकता है। इसलिए, कुंभ का सही उपयोग करना और इसे राजनीति से ऊपर रखना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि यह मेला अपनी मूल आत्मा – "विविधता में एकता" को साकार कर सके।

> प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वीआईपी संस्कृति खत्म करने के दावों के बावजूद, महाकुंभ में वीआईपी पासों का वितरण हुआ। इसने सामान्य श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना कराया, और प्रशासन की विफलता को उजागर किया।

****

लेखक मीडिया मैप के मुख्य सह - सम्पादक है।

कुंभ और गंगा सागर: राजनीतिक टकराव का कारण बने दो पवित्र आयोजन

प्रभजोत सिंह

भारत में आध्यात्मिकता को राजनीति से अलग माना जाता रहा है, लेकिन हाल की घटनाओं ने दिखाया है कि पवित्र अवसर भी राजनीतिक प्रभाव से अछूते नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला और पश्चिम बंगाल में गंगासागर मेला के बीच प्रतिस्पर्धा उभरकर सामने आई है। भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की पश्चिम बंगाल सरकार के बीच यह टकराव धार्मिक महत्व, संसाधनों और मान्यता को लेकर है।

कुंभ और गंगासागर मेले के बीच प्रतिस्पर्धा धार्मिक पहचान, राजनीति और आर्थिक प्रभाव का संघर्ष बन गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान कुंभ मेले को उजागर किया, लेकिन गंगासागर मेले का उल्लेख नहीं किया। इससे पश्चिम बंगाल सरकार का दावा मजबूत हुआ कि भाजपा कुंभ मेले को प्राथमिकता दे रही है। यह विवाद आध्यात्मिक पहचान के साथ आर्थिक लाभ, मीडिया कवरेज और सरकारी वित्तीय सहायता से भी जुड़ा है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर कुंभ मेले को समर्थन देने और गंगासागर मेले की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। उनकी सरकार गंगासागर को राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दिलाने के लिए प्रयासरत है।

कुंभ और गंगासागर मेले दोनों जनवरी में होते हैं और लाखों श्रद्धालु इनमें भाग लेते हैं। कुंभ मेला हर 12 साल में होता है और इस बार विशेष खगोलीय संयोग के कारण अधिक महत्व रखता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे भव्य आयोजन के रूप में प्रचारित किया है और 40 करोड़ श्रद्धालुओं की भागीदारी की उम्मीद है। दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल सरकार गंगासागर मेले को अधिक पहचान दिलाने के लिए प्रचार अभियान चला रही है। समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर इसके आध्यात्मिक महत्व को उजागर किया जा रहा है। तीर्थयात्रियों को प्रमाण पत्र देने की योजनाएं भी शुरू की गई हैं।

टीएमसी सरकार का तर्क है कि गंगासागर मेले को भी कुंभ मेले की तरह राष्ट्रीय महत्व और सरकारी सहायता मिलनी चाहिए। धार्मिक त्योहार अब राजनीतिक शक्ति और प्रभाव के प्रतीक बन चुके हैं। कुंभ और गंगासागर की प्रतिस्पर्धा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव से भी जुड़ी हुई है।

दो प्रमुख धार्मिक आयोजनों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक लाभ और संसाधनों की कड़ी जंग का प्रतीक बन गई है।

अंततः, कुंभ और गंगासागर मेलों की प्रतिस्पर्धा केवल धार्मिक प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक प्रभुत्व और आर्थिक लाभ की भी लड़ाई है। जब तक धार्मिक आयोजनों का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग होता रहेगा, तब तक ये पवित्र अवसर राष्ट्रीय बहस और प्रतियोगिता के केंद्र में बने रहेंगे।

****

लेखक वरिष्ठ पत्रकार है , खेल कूद पत्रकार्ता में उनकी विशेष रूचि है। और उन्होंने साथ ओलिंपिक कवर किये है। खेल - कूद के साथ ही व्यापर , विति , स्वास्थ , विमानन और सिख -पंजाब राजनीति के भी विशेषज्ञ माने जाते है।

भारत और राष्ट्रपति ट्रंप की नई अर्थव्यवस्था

गोपाल मिश्रा

भारतीय नीति निर्माताओं, चाहे वे विपक्ष में हों या सत्तारूढ़ दल में, को अमेरिका के बारे में अपनी वर्तमान धारणा को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति है, और 20 जनवरी को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के शपथ ग्रहण के साथ ही भारत के प्रति अमेरिकी नीति में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।

यह अमेरिका में रहने वाले भारतीय

> आलोक जगधारी ने चेतावनी दी कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी का असर भारत पर भी पड़ सकता है, साथ ही भारत को अमेरिका से तकनीकी सहयोग बढ़ाना होगा।

वेल्थ मैनेजर आलोक जगधारी का दृष्टिकोण था। उन्होंने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मीडिया के दिग्गजों, कॉरपोरेट के वरिष्ठ अधिकारियों, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं के समक्ष लगभग 90 मिनट की विस्तृत प्रस्तुति दी। यह प्रस्तुति 14 जनवरी 2025 की शाम को, न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरने से कुछ घंटे पहले दी गई थी। संभवतः वे व्हाइट हाउस में ट्रंप के ऐतिहासिक शपथ ग्रहण से पहले वाशिंगटन लौटने की जल्दी में थे।

इस सभा में फाइनेंशियल एक्सप्रेस के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री शिवाजी सरकार, वामपंथी विचारक डॉ. सतीश मिश्रा, पेप्सी की पूर्व सीईओ शिखा त्यागी, सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका रोमा मिश्रा, तथा मॉन्ट्रियल, कनाडा के वरिष्ठ पत्रकार केबी माथुर शामिल थे। इसका संचालन मीडिया मैप के संपादक प्रदीप माथुर ने किया, जिन्होंने गुटनिरपेक्षता पर एक पुस्तक भी लिखी है।

जब उनसे पूछा गया कि क्या नई दिल्ली को अमेरिका के साथ अपने संबंधों में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद करनी चाहिए, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिकी प्रणाली किसी भी राष्ट्रपति को स्थापित नीतियों से अधिक विचलित होने की अनुमति नहीं देती। उन्होंने भारतीय नीति निर्माताओं को आगाह किया कि निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नरेंद्र मोदी सरकार को कई रियायतें दी थीं, लेकिन अमेरिकी प्रतिष्ठान की अपनी नीतियां होती हैं, जो किसी भी व्यक्ति के प्रभाव से

> अमेरिका की नीतियों में किसी भी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं, भारतीय नीति निर्माताओं को समझना होगा कि वैश्विक महाशक्ति के एजेंडे को प्रभावित करने वाली ताकतें सीमित हैं।

सीमित रूप से प्रभावित होती हैं।

आलोक जगधारी ने कहा कि मोदी की छवि और उनकी सरकार के नागरिक स्वतंत्रता एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर दृष्टिकोण की समीक्षा आवश्यक है। उन्होंने नीति निर्माताओं को यह समझने की सलाह दी कि वैश्विक महाशक्ति के एजेंडे को प्रभावित करने वाली राजनीतिक और आर्थिक ताकतों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

उन्होंने याद दिलाया कि 20वीं सदी के शुरुआती तीसवें दशक में उच्च टैरिफ

लगाए गए थे, लेकिन अनुभव यह बताता है कि ऐसे उपाय राजनीतिक रूप से प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन वे संबंधित अर्थव्यवस्थाओं को स्थायी रूप से लाभ नहीं पहुंचाते। उन्होंने ट्रंप के कार्यकाल में सैन्य-औद्योगिक परिसर के प्रभाव को नियंत्रित करने की किसी भी संभावना को खारिज किया और चेतावनी दी कि ट्रंप अन्य राजनेताओं की तरह सत्ता के खेल में पूरी तरह शामिल हैं।

जब उनसे रूस-यूक्रेन युद्ध के भविष्य के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि इस संघर्ष के कई आयाम हैं, जिसमें यूरोपीय संघ की भूमिका भी शामिल है। उन्होंने कहा कि यूरोप और पश्चिम एशिया में किसी बड़े

> आलोक जगधारी का मानना है कि ट्रंप का दूसरा कार्यकाल अधिक सतर्क रहेगा, और भारत को अमेरिका के साथ अपने संबंध मजबूत करने की आवश्यकता है।

राजनीतिक घटनाक्रम की संभावना कम है।

चीन के प्रति अमेरिकी नीति पर उन्होंने कहा कि बीजिंग ने ताइवान के प्रति अपना दृष्टिकोण बदला है और यदि मौका मिला, तो वह इस द्वीप राष्ट्र का विलय करने में संकोच नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि यदि ताइवान स्वतंत्रता की घोषणा करता है, तो अमेरिका उसके बचाव की कोई गारंटी नहीं देगा। हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पनामा नहर में चीन की घुसपैठ से अमेरिकी प्रतिष्ठान चिंतित है।

आलोक ने कहा कि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में अधिक सतर्क रह सकते हैं। जब मोदी को ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण न दिए जाने पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि मोदी को डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत करीब समझा जाता है। इसी वजह से ट्रंप और उनके बीच संवाद में अनिच्छा देखने को मिली, जिससे उनके संबंधों में ठंडक आ गई। दूसरी ओर, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग वाशिंगटन के प्रोटोकॉल को लेकर आशंकित थे, इसलिए उन्होंने समारोह में शामिल न होने का फैसला किया।

भारत पर प्रभावआलोक जगधारी ने आगाह किया कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी का असर वैश्विक स्तर पर महसूस किया जाएगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। उन्होंने बताया कि भारत को अभी जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे साझेदारों की मान्यता नहीं मिली है। यह केवल एक सहयोगी के रूप में देखा जाता है।

उन्होंने कहा कि भारत को अत्याधुनिक तकनीक प्राप्त करने के लिए अमेरिका के साथ अपने संबंधों

> भारत के लिए अमेरिकी नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भारत को वैश्विक ताकतों का ध्यान रखना होगा।

को मजबूत करना होगा। अमेरिकी औद्योगिक इकाइयों के पुनरुद्धार की संभावना से इनकार करते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि भारत अमेरिकी कंपनियों के लिए एक नया पसंदीदा गंतव्य बन सकता है। हालांकि, इसके लिए भारतीय प्रौद्योगिकी को विश्व स्तरीय बनाना आवश्यक होगा।

जब उनसे समकालीन अमेरिकी समाज में लैंगिक मुद्दों के प्रभाव पर पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि इन सामाजिक विचलनों ने एक विकसित समाज में सामाजिक पतन को बढ़ावा दिया है। हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि इससे वैश्विक शक्ति संतुलन पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

****

लेखक : वरिष्ठ पत्रकार एवं पत्रकारिता शिक्षक है।

क्या कनाडा का प्रधान मंत्री भी भारतवंशी होगा?

प्रभजोत सिंह

रूबी ढल्ला, एक ऐसा नाम जो कनाडा की राजनीति में एक नई लहर का प्रतीक बनता जा रहा है। भारतीय मूल की इस महिला ने न केवल अपने देश में, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारतीय प्रवासियों की उपलब्धियों को नई पहचान दी है। हाल ही में, उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ एक तस्वीर साझा की और लिखा, "गर्व और भावना से भरा क्षण।" यह तस्वीर उनके लिए ऐतिहासिक थी, क्योंकि वह भारतीय मूल की पहली महिला हैं, जो कनाडा और पश्चिमी दुनिया में सांसद के रूप में निर्वाचित हुईं।

रूबी ढल्ला का राजनीतिक सफर 2004 में शुरू हुआ, जब उन्होंने ग्रेटर

> रूबी ढल्ला, भारतीय मूल की पहली महिला सांसद, ने कनाडा और वैश्विक स्तर पर भारतीय प्रवासियों की सफलता को नई पहचान दी है। उनकी राजनीतिक यात्रा 2004 में शुरू हुई और अब वह लिबरल पार्टी की नेता बनने की दौड़ में हैं।

टोरंटो एरिया (GTA) में ब्रैम्पटन-स्प्रिंगडेल राइडिंग का प्रतिनिधित्व किया। वह और नीना ग्रेवाल, दोनों हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठने वाली भारतीय मूल की पहली महिलाओं में शामिल हुईं। रूबी ने लिबरल पार्टी का प्रतिनिधित्व किया, जबकि नीना ने कंजर्वेटिव पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसने भारतीय समुदाय में गर्व और उत्साह पैदा किया।

एक सांसद के रूप में, रूबी ढल्ला ने युवा वर्ग के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनके भाई नील की मृत्यु ने उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया। नील की याद में आयोजित एक कार्यक्रम में, उन्होंने भावनात्मक रूप से कहा, "आज दो साल हो गए... जीवन बदल गया... मेरा भाई, सबसे अच्छा दोस्त, गुरु, प्रेरणा और हमारे घर का स्तंभ भगवान के पास चला गया।" यह अनुभव उनके लिए एक प्रेरणा बन गया और उन्हें राजनीति में लौटने की शक्ति दी।

अब, रूबी ढल्ला ने राजनीति में वापसी की योजना बनाई है और लिबरल पार्टी की नेता बनने के लिए चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। हाल ही में एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि वह इस दौड़ में एकमात्र ऐसी उम्मीदवार हैं जिनका ट्रूडो सरकार से कोई संबंध नहीं है। उनका मानना है कि पार्टी को फिर से केंद्र की ओर लौटने की आवश्यकता है।

अपने सोशल मीडिया पर, उन्होंने खुद को एक "अग्रणी, होटल व्यवसायी,

> रूबी ढल्ला ने अपने जीवन के कठिन समय, जैसे अपने भाई की मृत्यु, को अपनी प्रेरणा में बदला और राजनीति में वापसी करने का संकल्प लिया। उनका मानना है कि कनाडा को एक नई दिशा की आवश्यकता है, और वह इसे केंद्र की ओर लौटाने के लिए तैयार हैं।

परोपकारी और प्रेरक वक्ता" के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, "एक स्व-निर्मित व्यवसायी के रूप में, मुझे हमारे देश में व्यवसाय मालिकों और उद्यमियों के संघर्षों और बलिदानों की गहरी समझ है।" यह उनके अनुभव को दर्शाता है, जो उन्हें राजनीति में एक नई दृष्टि देने में सहायक होगा।

रूबी ढल्ला ने अपने होटल व्यवसाय में बदलाव के बारे में भी बात की। उन्होंने लिखा, "सबसे अच्छा शिक्षक हमेशा जीवन और अनुभव होता है, और सबसे अच्छी शिक्षा तब मिलती है जब आप प्रतिकूल परिस्थितियों और त्रासदी का सामना करते हैं।" यह

उनके जीवन के अनुभवों को दर्शाता है, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं।

अपनी राजनीतिक वापसी के साथ, उन्होंने लिबरल पार्टी के नेतृत्व अभियान को आक्रामक ढंग से आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा, "मुझे यह विडंबनापूर्ण लगता है कि नेता बनने की चाहत रखने वाले सभी लोग, जो उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने पिछले 10 साल इन सभी नीतियों को बनाने और विकसित करने में बिताए हैं।" उनका यह बयान पार्टी के भीतर की स्थिति को स्पष्ट करता है और यह दिखाता है कि वह बदलाव की आवश्यकता को समझती हैं।

उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों पर भी निशाना साधा और कहा, "जिन लोगों ने सिस्टम को तोड़ा है, वे निश्चित रूप से इसे ठीक नहीं कर सकते" और "लिबरल पार्टी टूट चुकी है। हमें सिस्टम को साफ करना होगा।" यह उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है कि वह पार्टी को एक नई दिशा में ले जाने के लिए तैयार हैं।

उनकी वापसी के साथ, भारतीय मूल के कनाडाई नागरिकों में एक नई उम्मीद जगी है। क्या वह लिबरल पार्टी के नेतृत्व की दौड़ को प्रभावित करेंगी? यह सवाल हर भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक के मन में है। रूबी ढल्ला ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कहा, "कनाडा की वापसी अब शुरू हो रही है।"

उन्होंने अपने राजनीतिक और व्यावसायिक अनुभव का बखान करते हुए कहा, "पार्टी के नेता के रूप में मैं जो पहला काम करूंगी, वह यह सुनिश्चित करना है कि हम केंद्र की ओर वापस लौटें, केंद्र के दाईं ओर, क्योंकि मुझे लगता है कि यही समय की मांग है।"

> रूबी ढल्ला ने अपने होटल व्यवसाय और राजनीतिक अनुभव का उपयोग कर लिबरल पार्टी को एक नई दिशा देने का वचन दिया है। उनका बयान है कि "सिस्टम को तोड़ने वाले इसे ठीक नहीं कर सकते," और वह पार्टी में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

अपनी नवीनतम पोस्ट में उन्होंने कहा, "मैं रूबी ढल्ला हूं और मैं इसलिए चुनाव लड़ रही हूं क्योंकि हमें पियरे पोलीवरे और कंजर्वेटिव को हराना है।" यह स्पष्ट करता है कि वह केवल अपनी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि पूरे कनाडा के लिए एक नई दिशा की तलाश कर रही हैं।

लिबरल पार्टी के अध्यक्ष सचित मेहरा ने कहा, "लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा एक सुरक्षित, निष्पक्ष और मजबूत नेतृत्व की दौड़ में भाग लेने के लिए तैयार है।" यह दर्शाता है कि पार्टी में एक नई ऊर्जा और उत्साह है, जो रूबी ढल्ला जैसे नेताओं के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है।

रूबी ढल्ला की कहानी केवल एक राजनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणा भी है। उनकी मेहनत, संघर्ष और दृढ़ संकल्प ने उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया है। अब, जब वह राजनीति में वापसी कर रही हैं, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि वह लिबरल पार्टी को किस दिशा में ले जाती हैं और क्या वह कनाडा की अगली प्रधानमंत्री बन पाएंगी।

उनकी यात्रा ने यह साबित कर दिया है कि जब आप अपने सपनों के लिए संघर्ष करते हैं, तो कुछ भी संभव है। रूबी ढल्ला का नाम अब केवल एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में भी जाना जाएगा। उनके प्रयासों से न केवल भारतीय समुदाय को बल्कि सभी कनाडाई नागरिकों को एक नई दिशा मिलेगी।

इस प्रकार, रूबी ढल्ला की कहानी एक नई शुरुआत की प्रतीक है, जो न केवल उनके लिए, बल्कि पूरे कनाडा के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। क्या वह अपने सपनों को साकार कर पाएंगी? यह तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन उनकी मेहनत और संघर्ष ने उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया है, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है।

****

लेखक वरिष्ठ पत्रकार है , उन्होंने साथ ओलिंपिक कवर किये है। खेल - कूद के साथ ही व्यापर , वित्ति , स्वास्थ , विमानन और सिख -पंजाब राजनीति के भी विशेषज्ञ माने जाते है।

स्वतंत्रता आंदोलन में गांधीजी के योगदान को कमतर आंकने का प्रयास

राम पुनियानी

इतिहासकार एरिक हॉब्सवैम ने कहा था कि इतिहास राष्ट्रवाद के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अफीम के आदी व्यक्ति के लिए पोस्ता। दक्षिणपंथी तेजी से अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें इतिहास को विकृत करके कुछ लोगों को बाहर करने और दूसरों का महिमामंडन करने का प्रयास किया जाता है। विशेष रूप से मध्यकालीन भारतीय इतिहास को इस्लामी साम्राज्यवाद का युग बताकर मुस्लिम शासकों को गलत तरीके से पेश किया गया, जिससे आज के मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काने में मदद मिली। प्राचीन इतिहास को भी इस तरह बदला गया कि आर्यों को इस भूमि के मूल निवासी दिखाया जा सके।

स्वतंत्रता संग्राम में धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक नेहरू को दक्षिणपंथी विचारकों ने निशाने पर लिया। नेहरू ने बहुसंख्यक सांप्रदायिकता को फासीवाद के बराबर बताया था और अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता को अलगाववाद से जोड़ा था। गांधी की हत्या करने वाले व्यक्ति का संबंध हिंदू महासभा और आरएसएस से था, लेकिन गांधी की वैश्विक छवि के कारण उन्हें शैतान बनाना मुश्किल था।

अब दक्षिणपंथी ताकतें गांधी की छवि को धूमिल करने के प्रयासों में लगी हैं। 30 जनवरी 2025 को जब पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा था, कई पोर्टल्स और सोशल मीडिया चैनलों पर यह प्रचार किया जा रहा था कि गांधी के प्रयासों से भारत को आजादी मिलने में मामूली योगदान था। हाल के वर्षों में 'महात्मा गोडसे अमर रहें' जैसे नारे भी देखने को मिले हैं। महाराष्ट्र सरकार के इस वर्ष के परिपत्र में गांधी का नाम तक नहीं लिया गया।

गांधी को 'महात्मा' की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। यह भी प्रचारित किया जाता है कि

> "गांधी, स्वतंत्रता संग्राम और इतिहास विकृति के खिलाफ सच्चाई की पड़ताल।"

कांग्रेस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अनदेखी की, जबकि नेताजी ने ही गांधी को 'राष्ट्रपिता' कहा था और अपनी सेना की एक बटालियन का नाम गांधी बटालियन रखा था। कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज के कैदियों के मुकदमे लड़ने के लिए एक वकीलों की समिति भी बनाई थी। इसी तरह, यह भी कहा जाता है कि गांधी ने भगत सिंह की फांसी को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, जबकि उन्होंने लॉर्ड इरविन को पत्र लिखकर फांसी रोकने का आग्रह किया था।

गांधी के आंदोलनों की भी आलोचना की जाती है। 1920 का असहयोग आंदोलन आम जनता को संघर्ष में शामिल करने का पहला बड़ा प्रयास था, जिसे चौरी चौरा घटना के कारण वापस ले लिया गया। खिलाफत आंदोलन के समर्थन को भी गलत बताया जाता है, जबकि यह ब्रिटिश विरोधी संघर्ष का हिस्सा था और इससे मुसलमानों को स्वतंत्रता संग्राम में जोड़ा गया। मप्पिला विद्रोह को हिंदुओं के खिलाफ बताया जाता है, जबकि यह गरीब मुस्लिम किसानों का जमींदारों के खिलाफ विद्रोह था।

1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी-इरविन समझौता स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने वाला कदम था। नमक सत्याग्रह से नमक कर पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, लेकिन यह गैरकानूनी नहीं रहा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को हिंसक बताया जाता है, लेकिन इसने आजादी की लहर को तेज किया और जनचेतना का निर्माण किया। स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और क्रांतिकारियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन गांधी ने भारतीयता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसे 'भारत: राष्ट्र निर्माण' कहा था। स्वतंत्रता संग्राम केवल अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष नहीं था, बल्कि भारत को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने की प्रक्रिया भी थी। दक्षिणपंथी ताकतें इस पहलू को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही हैं, जबकि यही कारण है कि गांधी को सही मायनों में 'राष्ट्रपिता' कहा जाता है।

****

लेखक वरिष्ठ पत्रकार है।

जनवरी 30 : महात्मा गांधी बलिदान दिवस

बापू की सरलता और सादगी तथा यह वैभव और प्रदर्शन की संस्कृति

जगदीश गौतम

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी को लेकर संघ परिवार की विचारधारा में अजीब सा विरोधाभास है। वह महात्मा गाँधी की हिन्दू छवि को तो पसंद करते है पर वह उनकी सर्वधर्म सम्भाव की नीति को गले नहीं उतार पाते। उन्हें यह बात बुरी लगती है कि राम की माला जपने के बाद भी महात्मा गाँधी मुस्लिम विरोधी क्यों नहीं थे। फिर कटु सत्य यह भी है कि 'जाति पात पूछे नहीं कोई, हिन्दू कहे तो हिन्दू होई' का नारा देने के बाद भी संघपरिवार उच्च हिन्दू जाति वर्ग का ही हित साधन करती है और उसे दलित या जनजातीय हिन्दू वर्ग से कोई लगाव नहीं है जबकि महात्मा गाँधी आजीवन दलित उत्थान में लगे रहे।

महात्मा गाँधी को ह्रदय से न पसंद करने के बाद और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे के लिए समस्त स्नेह और सहानभूति रखने के बाद भी संघपरिवार वोट बैंक खोने और चुनाव हारने के डर से महात्मा गाँधी का खुला विरोध करने से कतराते है। इसी कारण भाजपा के बड़े नेता समय समय पर महात्मा गाँधी का नाम लेते रहते है।

पिछले दिनों भाजपा नेतृत्व ने दावा किया कि मोदी की सरकार सच्चे रूप में महात्मा गाँधी के दिखाए रास्ते पर चल रही है। उदाहरण स्वरूप उसने यह कहा कि प्रधानमंत्री का स्वच्छता अभियान तथा सबका साथ सबका विकास इसका स्पष्ट उदाहरण है।

पर भाजपा का नेतृत्व मूल गया कि महात्मा गाँधी सरलता और सादगी का भी प्रतीक थे और भाजपा को दिखावे तथा वैभव की संस्कृति से वह कोसो दूर थे। वास्तव में संघपरिवार किसी भी तरह दूर दूर तक गाँधीवादी विचारधारा का पोषक नहीं है। इसके विपरीत वह गाँधी विरोधी है।

महात्मा गाँधी के बलिदान दिवस के अवसर पर प्रश्न यह नहीं है कि इस कालजयी महापुरुष के द्वारा स्थापित मानवतावादी

मूल्यों का किस प्रकार से प्रसार-प्रचार किया जाय जिससे वह हमारी व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का आधार बन सकें। चुनौती इस बात की है कि कुछ निहित स्वार्थी और विवेक शून्य लोगों द्वारा गांधीवाद की हत्या के प्रयास को किस तरह विफल जाय।

वास्तव में यह प्रयत्न दुर्भाग्यपूर्ण है जिस महापुरुष के "सत्य और अहिंसा" पर चलने के मार्ग को तमाम विश्व में ख्याति मिली और तमाम बड़े लोगों ने जिसे अपना आदर्श माना। उसी गांधी की आज कुछ लोगों द्वारा उनके अपने ही देश में छवि खराब करने की साजिश की जा रही है और उनके हत्यारे जो भारतीय संस्कृति व मानवता का हत्यारा था, की स्तुति की जा रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात हमारे लिए कुछ और नहीं हो सकती।

एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि गांधीवाद की हत्या का प्रयास करने वाले ये लोग कोई भी हो, ये न तो सच्चे हिंदू हैं और न ही हिंदू समुदाय के हितैषी। यदि इनको न रोका गया और इनके गतिविधियों को बंद नहीं गया तो आने वाले दिनों में ये हिंदू समाज और देश का बहुत बड़ा अहित करेगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि आवश्यक कानून बना कर गांधी पर बेतुके और शर्मनाक लांछन लगाने तथा उनके हत्यारों को महिमामंडित करने के समस्त प्रयासों को अविलंब दंडनीय अपराध घोषित किया जाय।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम और उपनिवेशवादी मानसिकता के विरुद्ध महात्मा गांधी का योगदान अद्वितीय है। महात्मा गांधी का अपमान राष्ट्र का अपमान है। वह किसी दल या समुदाय का प्रतिनिधि न होकर समस्त भारतीयता के प्रतीक थे। यह बड़ी अजीब बात है कि महात्मा गांधी के ये विरोधी अपने को राष्ट्रवादी होने का दम भरते रहते हैं।

अब समय आ गया है कि अपने को राष्ट्रवादी कहने वाले इन छद्म शत्रुओं को तुरंत चिह्नित किया जाय और उन्हें कड़ा से कड़ा दंड दिया जाय। जिससे हमारे स्वाधीनता संग्राम की गरिमा और हमारे देश का सम्मान अक्षुण्ण बना रहे।

****

लेखक मीडिया मैप के मुख्य प्रबंधक हैं।

कैंसर रोग की चिकित्सा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता

पवन सिंह

कैंसर के निदान और उपचार के लिए अधिक से अधिक अस्पतालों की आवश्यकता है, क्योंकि इस बीमारी से मुक्ति पाने के लिए केवल अच्छे चिकित्सक और उन्नत चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने जो चेतावनी दी है, वह बेहद चिंताजनक है। ICMR का अनुमान है कि 2025 तक भारत में कैंसर के मामलों में 12.7 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। चीन के बाद, भारत में कैंसर के मरीजों की संख्या सबसे तेजी से बढ़ रही है। देश

> भारत में कैंसर के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, और ICMR की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 तक 12.7% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके बावजूद, कैंसर के इलाज के लिए पर्याप्त सरकारी अस्पतालों की कमी और महंगे इलाज की समस्या गंभीर हो रही है।

में कैंसर के हालात गंभीर होते जा रहे हैं। ICMR के अनुसार, 2020 में भारत में कैंसर के अनुमानित मामले 13.92 लाख थे, जो 2021 में बढ़कर 14.26 लाख और 2022 में 14.61 लाख तक पहुंच गए।

ICMR की रिसर्च ने यह भी साबित किया है कि वायरल इन्फेक्शन भी अब कैंसर के उत्पन्न होने के प्रमुख कारणों में से एक बन चुका है। HPV (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) जैसे वायरस लिंग, योनि, मुंह और गले के कैंसर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ICMR की स्टडी के अनुसार, यदि यही प्रवृत्ति जारी रही, तो हर 9 भारतीयों में से एक को अपने जीवनकाल में एक बार कैंसर होने का खतरा रहेगा। इसके अलावा, ICMR के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर 68 पुरुषों में से एक को फेफड़े का कैंसर होगा, जबकि हर 29 में से एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है।

भारत में 2020 में 50,000 कैंसर के मामले केवल शराब पीने के कारण दर्ज हुए थे। इसके बावजूद सरकारें शराब सिंडीकेट के साथ मिलकर लगातार शराब के ठेके खोल रही हैं और आबकारी अधिकारियों को राजस्व बढ़ाने का निर्देश दे रही हैं। जो राज्य शराब मुक्त थे, वहां भी शराब बेची जा रही है। यह स्थिति चिंताजनक

> देश में कैंसर का इलाज महंगा और पहुंच से बाहर होता जा रहा है। रेडियोथेरेपी जैसी महत्वपूर्ण चिकित्सा सुविधा केवल कुछ अस्पतालों में उपलब्ध है, और हर 10 लाख की आबादी पर रेडियोथेरेपी मशीनों की संख्या बेहद कम है।

है क्योंकि भारत कैंसर के मामलों में अब चीन के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है। भारत में ओरल कैविटी के कैंसर के 38.76 प्रतिशत, एसोफेगस के 26.4 प्रतिशत, फैरिंक्स के 12.4 प्रतिशत, लैरिंक्स के 6.2 प्रतिशत, लीवर के 6 प्रतिशत और अन्य 10.3 प्रतिशत कैंसर देखे जा रहे हैं, जिनमें से अधिकांश शराब जनित कैंसर हैं। इसके अलावा, मोटापे से होने वाले कैंसर की संख्या भी बढ़ रही है, जिसमें एंडोमेट्रियल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, पेट का कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर, किडनी कैंसर, रेक्टल कैंसर, पेनक्रिएटिक कैंसर, इसोफेजियल एडेनोकार्सिनोमा और ओवेरियन कैंसर शामिल हैं।

रिसर्च के अनुसार, 2020 में एशिया में कैंसर के 15 लाख नए मामले सामने आए थे, जिनमें हेलिकोबैक्टर पाइलोरी (52.1 प्रतिशत), HPV वायरस (19.1 प्रतिशत), हेपेटाइटिस बी वायरस (10.8 प्रतिशत), हेपेटाइटिस सी वायरस (7.5 प्रतिशत) और अन्य कारण (10.6 प्रतिशत) शामिल थे। भारत में तम्बाकू जनित कैंसर ने भी तेजी से बढ़त हासिल की है। फेफड़े का कैंसर और सिर व गर्दन के कैंसर ने भारत में खतरनाक वृद्धि की है। 2020 तक भारत में 6 लाख 79 हजार 421 पुरुष कैंसर से ग्रस्त थे, और 2025 तक इस आंकड़े के बढ़कर 7 लाख 63 हजार 575 तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं, 2020 में कैंसर पीड़ित महिलाओं की संख्या 7 लाख 12 हजार 758 थी।

कैंसर का इलाज अत्यधिक महंगा है और सरकारी स्तर पर चिकित्सा व्यवस्था धीरे-धीरे कारपोरेट सेक्टर की ओर बढ़ रही है। यदि आप शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के मामलों से ज्यादा चिंतित नहीं हैं, तो कोई नहीं जानता कि आप कब इस भयावह बीमारी की "यमराजीय" पकड़ में आ जाएंगे। कैंसर के बढ़ते मामलों के बावजूद, देश के केवल 50 सरकारी अस्पतालों में ही रेडियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। कैंसर मरीजों की संख्या हर साल तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उपचार की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। दिल्ली समेत देश भर में कैंसर का इलाज महंगे निजी अस्पतालों के पास ही है। इन अस्पतालों में रेडिएशन थेरेपी की कीमत काफी अधिक है, और महंगे इलाज और चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में कई मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित संसदीय कमेटी की रिपोर्ट में भी रेडिएशन थेरेपी की उपलब्धता पर सवाल उठाए गए हैं, और इस सुविधा के अभाव के कारण औसतन केवल 20 प्रतिशत मरीजों को ही यह मिल पाती है।

> कैंसर के बढ़ते मामलों के बीच, शराब और तंबाकू जैसे कारणों के चलते कैंसर के नए मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, 2020 तक भारत में कैंसर के 14 लाख नए मामले सामने आए, जिनमें शराब और तंबाकू से जुड़ी बीमारियाँ प्रमुख हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, हर 10 लाख की आबादी पर एक रेडियोथेरेपी मशीन होनी चाहिए। अगर इस मानक को आधार माना जाए तो देश में लगभग 1,300 रेडियोथेरेपी मशीनों की आवश्यकता है, लेकिन हकीकत यह है कि देश में केवल 700 मशीनें उपलब्ध हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों को मिलाकर पूरे देश में लगभग 250 अस्पतालों में ही रेडियोथेरेपी की सुविधा है, जिसमें से लगभग 200 निजी अस्पताल हैं। यह स्थिति चिकित्सा सुविधाओं पर गंभीर सवाल खड़े करती है। दिल्ली में सिर्फ तीन सरकारी अस्पतालों में गरीब कैंसर मरीज इलाज करा सकते हैं, और दिल्ली के 22 अस्पतालों में रेडिएशन थेरेपी होती है, जिनमें एम्स, सफदरजंग, दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान, लोकनायक, आर्मी अस्पताल और आइएलबीएस जैसे अस्पताल शामिल हैं।

सफदरजंग अस्पताल में रेडियोथेरेपी के लिए तीन कोबाल्ट मशीनें हैं, जिनमें से दो अक्सर खराब रहती हैं। यहां केवल एक मशीन काम करती है, और वह भी कई बार खराब हो जाती है। इसके विपरीत, निजी अस्पतालों में रेडियोथेरेपी का खर्च दो लाख से ढाई लाख रुपये तक हो सकता है, जबकि एम्स में इसकी लागत लगभग 8 हजार रुपये है। भारत में कैंसर विशेषज्ञों की भी भारी कमी है, और देश में हर दस लाख की आबादी पर एक मेडिकल आंकोलाजी विशेषज्ञ और 1.5 रेडिएशन आंकोलाजी विशेषज्ञ हैं, जो एक अत्यंत शर्मनाक स्थिति है।

इसलिए, यदि हमें इस भयावह बीमारी के प्रति गंभीरता से काम करना है, तो हमें चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार की सुविधाओं पर ध्यान देना होगा।

****

लेखक स्वतंत्र पत्रकार है।

अनूप श्रीवास्तव जो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे

रामकिशोर उपाध्याय

गत बीस जनवरी को बहुमुखी प्रतिभा के धनी हिंदी साहित्य और व्यंग्य पत्रकारिता के आधार स्तम्भ अनूप श्रीवास्तव के दुखद समाचार ने मुझे ही नहीं उनके परिवार, मित्रों और साहित्यकारों को स्तब्ध कर दिया | अभी दो –तीन पहले से उनसे मेरी बात हुई थी तब कहीं से यह नहीं लगता था वे अचानक इस नश्वर संसार को छोड़ जायेंगे | मैं उनके पास लखनऊ मिलने जाने का कार्यक्रम बना ही रहा था, लेकिन यह इच्छा अधूरी ही रह गयी ,शायद यही नियति को मंजूर था | मैं 2015 के विश्व पुस्तक मेले का वह दिन याद करता हूँ जब मेरा नेशनल बुक ट्रस्ट के संपादक ललित लालित्य ने अनूप श्रीवास्तव जी से मेरा परिचय कराया था | उसके बाद मेरा उनसे सम्बन्ध दिन प्रतिदिन प्रगाढ़ होता गया | मुझे उन्होंने अनुजवत स्नेह दिया | यह उनका विश्वास ही था कि उन्होंने मुझ जैसे अनाम साहित्यकार को देश की प्रसिद्द व्यंग्य पत्रिका 'अट्टहास' का कार्यकारी संपादक का कार्यभार दे दिया | उनके जाने से मेरी व्यक्तिगत क्षति का अनुमान करना कठिन है - वे मेरे बड़े भाई , संरक्षक और मार्गदर्शक बन गए थे | वे एक संकेत मात्र पर मेरे साथ कहीं भी जाने के लिए तत्पर रहते थे | अभी नवम्बर में हम दोनों कादम्बरी सम्मान लेने के लिए तीन दिन तक जबलपुर में साथ रहे | उनके साथ केवल मीठी ही यादें ही जुडी और मेरे और उनके बीच कभी कोई विवाद ही नहीं हुआ | किसी भी विषय पर या तो वे मेरी बात से या मैं उनसे सहमत हो गया | इन दस सालों में हमने उनके निर्देशन में भारत भर में अट्टहास के कई सफल कार्यक्रम आयोजित किये | उन्होंने मुझे मासिक 'अट्टहास' में सम्पादकीय लिखने की पूरी स्वतंत्रता दी | मुझे यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि एक व्यंग्यकार के रूप में उन्होंने मुझे तराशा है |

एक पत्रकार के रूप में हिंदी दैनिक गोरखपुर, स्वराज्य टाइम्स, नीहारिका, दैनिक भास्कर झांसी और इंदौर,दैनिक मध्यदेश, डेली एक्शन कानपुर , दैनिक जनवार्ता के पश्चात लगभग चालीस वर्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रसिद्ध अखबार स्वतंत्र भारत के मुख्य संवाददाता और सम्पादक रहे । अनूप श्रीवास्तव जी पिछले पांच दशकों से अधिक समय तक पत्रकारिता के बदलते इतिहास के चश्मदीद गवाह रहें |बाल कल्याण अनुसन्धान परिषद की प्रसिद्ध बाल पत्रिका 'गिलहरी'के सम्पादक रहे।

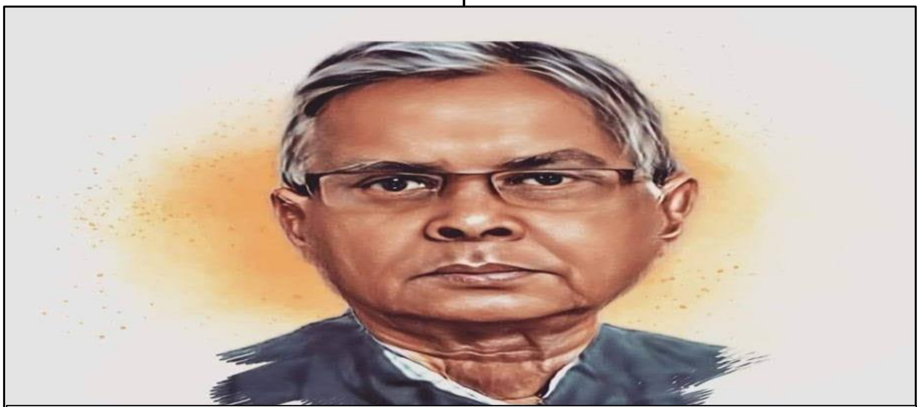

अनूप श्रीवास्तव (1944 – 2025)

पत्रकारिता की लंबी पारी खेलते हुए और व्यंग्य साहित्य को स्थापित करने में उनका अतुल्य योगदान है । अगर उन्हें व्यंग्य लेखन का कुलाधिपति कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । उन्होंने देश के पहले आध्यात्मिक चैनल "आस्था" की स्थापना की | आपने डॉ हरिवंश राय बच्चन ,डा शिवमंगल सिंह सुमन,डॉ विद्या निवास मिश्र, ठाकुर प्रसाद सिंह,डा चन्द्रदेव सिंह के निर्देश पर तिरसठ वर्ष पूर्व देश की प्रसिद्ध संस्था माध्यम साहित्यिक संस्थान की स्थापना की और अंतिम समय तक उसके महासचिव का कार्य सँभालते रहें ।

माध्यम साहित्यिक संस्थान अपने विशाल आयोजनोंके कारण देश ही नहीं विदेशों में भी जानी जाती है । यही नहीं अनूप जी ने पिछले पच्चीस वर्षो से प्रसिद्ध व्यंग्य पत्रिका 'अट्टहास हास्य व्यंग्य मासिक' बिना ब्रेक के निकालकर साहित्यिक पत्रिका का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया | अट्टहास को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने में उनका अप्रतिम योगदान है । वे स्वयं किसी भी सम्मान को लेने से बचते रहे | 2023 में युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच ने उन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र शिखर सम्मान दिया तो उन्होंने अपने खाते में एक पैसा नहीं लिया अपितु ग्यारह हज़ार रूपये की पुरस्कार राशि को अट्टहास पत्रिका के खाते में जमा करा दी | यह उनकी साहित्य और अट्टहास पत्रिका के लिए समर्पण भी भावना का ज्वलंत उदाहरण है | यही नहीं माध्यम साहित्यिक संस्थान के बैनर तले पैतालीस साल तक 'अट्टहास शिखर' और 'अट्टहास युवा सम्मान' देने का भी वे एक कीर्तिमान बना दिया | ये दोनों सम्मान हिंदी साहित्य में आज सर्वाधिक गौरवशाली सम्मान माने जाते हैं । शरद जोशी ,मनोहर श्याम जोशी,लतीफ घोंघी, गोपाल प्रसाद व्यास,डॉ नरेंद्र कोहली, रवीन्द्र नाथ त्यागी,डॉ ज्ञान चतुर्वेदी ,डॉ प्रेम जनमेजय,डॉ हरीश नवल, सूर्यबाला,माणिक वर्मा, सुभाष चंदर, बलराम और सुरेश कान्त सहित साठ से अधिक व्यंग्य लेखकों को उन्होंने अभी तक सम्मानित किया हैं | इसके साथ ही वे धर्मयुग, साप्ताहिक हिदुस्तान, दिनमान, कादम्बिनी, रविवार अंग्रेजी पाक्षिक 'प्रोब'के नियमित लेखन से जुड़े रहे |

अनूप जी लखनऊ महोत्सव,कुम्भ महोत्सव, गंगा महोत्सव, मंसूरी महोत्सव जैसे स्थापित आयोजनों के संयोजक के रूप में दस हज़ार से अधिक कविसम्मेलनों के सूत्रधार रहें | लगभग छत्तीस वर्षों तक काँव काँव कालम लिखने के साथ ही घाघ लखनवी तीरंदाज, बैठे ठाले आदि उपनामों से व्यंग्य लेखन की अमिट छाप छोड़ी है | उनकी अनुशंसा से उत्तरप्रदेश सरकार के द्वारा 'अट्टहास' के कार्यक्रमों को लगातार सरकारी कार्यक्रम के रूप में चालीस वर्ष तक निरंतर आयोजित किया गया तथा सभी उपस्थित साहित्यकारों को राज्य का अतिथि बनाया गया | मैं भी इन आयोजनों में राज्य अतिथि रह चुका हूं | यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि अनूप श्रीवास्तव जी के खाते में बड़ी सम्मान के साथ दर्ज है | पल-पल साहित्य जीने वाले 82 वर्षीय वरिष्ठ पत्रकार कवि और लेखक अनूप श्रीवास्तव की रचना यात्रा कभी नहीं थकी , बल्कि अंतिम समय तक जारी रही | सम्पूर्ण हिंदी साहित्य विशेषकर काव्य एवं व्यंग्य विधा को उनका अवदान युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत है । हिंदी साहित्य विशेषकर व्यंग्य लेखन के विकास और विस्तार के क्षेत्र में उनके जाने से हुई क्षति को बहुत देर तक महसूस किया जाता रहेगा | अनूप श्रीवास्तव व्यंग्य नर्सरी के एक कुशल माली के रूप में सदैव याद किये जायेंगे| अनूप श्रीवास्तव जी ने अपने जीवन को भरपूर जिया और हर संघर्ष को उन्होंने हँस –हँस कर झेला | उनकी व्यक्तिगत और साहित्य के प्रति निष्ठा सदैव असंदिग्ध रही,मेरा ऐसा मत है | अपने मित्रों और शुभचिंतकों के मध्य उनकी मीठी –मीठी यादों की कसक सदैव बनी रहेगी | उनके परिवार को अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हुए मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ |

> हिंदी व्यंग्य और पत्रकारिता के स्तंभ अनूप श्रीवास्तव जी का जाना अपूरणीय क्षति है। उनका जीवन साहित्य, पत्रकारिता और हास्य-व्यंग्य के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक था। "अट्टहास" जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका से लेकर हजारों साहित्यिक आयोजनों तक, उन्होंने व्यंग्य लेखन को एक नई ऊंचाई दी। वे सच्चे मार्गदर्शक, संरक्षक और प्रेरणास्रोत थे। उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा।

****

लेखक: भारतीय रेलवे के सेवा निवृत्त आई.आर.ए.एस अधिकारी हैं | उनकी रचनाएँ देश की अनेक पत्र -पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं । उनके पांच कविता संग्रह, दो व्यंग्य संग्रह,एक संस्मरण और एक विदेश-यात्रा संस्मरण प्रकाशित हो चुके हैं | वह हिंदी व्यंग्य की प्रतिष्ठित मासिक पत्रिका 'अट्टहास'के कार्यकारी सम्पादक हैं |

व्यंगकार अनूप और उनके कल्लू मामा

गोपाल मिश्र

आपके समक्ष व्यंग्य लेखन के पुरोधा अनूप श्रीवास्तव जी के बारे में अपार दुःख में डूबे कल्लू मामा की निजी डायरी के कुछ पृष्ठ प्रस्तुत कर रहा हूं। चूंकि अनूप जी ने न कल्लू मामा की क्षमता को पहचाना था और खुल कर लिखने का अवसर दिया, इसलिए अब वह किसी और मालिक को मुंह नहीं लगाना चाहते । अनूप जी से पूर्व न कल्लू मामा की क्षमता को शायद ही किसी ने पहचाना हो। अनूप जी के जाने के बाद न कल्लू मामा की कहानी अधूरी रह गई है। अब पता नहीं उनकी पुत्री शिल्पा कल्लू मामा की क्षमता पहचान सकेंगी या नहीं ।

कल्लू मामा की डायरी में नव लेखन को पुरस्कृत करने की चर्चा विस्तार से की गई है। पुराने मठाधीशों के साथ साथ जब कल्लू मामा को भी चर्चा में भाग लेने का अवसर मिला तो उसने भी खुल कर काव काव किया ।

अनूप श्रीवास्तव जी उस युग के प्रतीक थे, जब भारत में राष्ट्र भक्तों का शासन स्थापित हो चुका था। इन संस्कारी शासकों ने एक ऐसी राज्य व्यवस्था स्थापित कर दी थी कि उनके अनुसार हर मर्ज का इलाज योग गुरुओं के पास था। विज्ञान पढ़ना या पढ़ाना गोवध के समक्ष पाप समझा जाता था। इसने सिर्फ अनूप जी को बेदखल नहीं किया गया, उनके अनन्य मित्र एवं साथी स्वर्गीय राजेन्द्र द्विवेदी, जो कि दैनिक आज के संपादक रह चुके थे, और संस्कारी सरकार के संरक्षक माने जाते थे, उनको अस्पताल में इलाज कराने के बजाय संस्कारी सरकार की ओर से गोमूत्र एवं पंचगव्य की निःशुल्क व्यवस्था का ऑफर दिया गया। लेकिन उनकी धर्म पत्नी ने सनातनी परम्परा के खिलाफ अंग्रेजी दवाओं से इलाज कराया। और फिर भी उन्हें धरती छोड़नी पड़ी। एक राष्ट्र भक्त ने शोकाकुल स्वरों में कहा अगर पंचगव्य लेते तो भगवान इंद्र उन्हें स्वयं सम्मानित करते।

इसी प्रकार का ऑफर,अनूप जी के निर्देशानुसार, कल्लू मामा राष्ट्र भक्तों का संदेश लेकर संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं पत्रकार राजेन्द्र जी के पास गये थे। उनकी पत्नी ने भी संदेशवाहक को डांट कर भगा दिया।

इससे पूर्व स्वतंत्र भारत के संपादक एवं सांसद रहे राजनाथ सिंह ने, जो कि संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी रहे थे,अपना भौतिक शरीर लखनऊ के मेडिकल कॉलेज को देने की घोषणा की थी। इसके खिलाफ सनातन धर्म की ओर से फतवा जारी कर दिया गया। इसे अटल परंपरा के विरुद्ध माना गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि अटल जी को अस्पताल में तबतक रखा गया जबतक

अनूप श्रीवास्तव: व्यंग्य लेखन का अनमोल सितारा

अनूप श्रीवास्तव जी ने अपने बेबाक और निर्भीक व्यंग्य लेखन से हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। उनके प्रशंसकों में बड़े राजनेता और साहित्यकार शामिल थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी का पक्ष नहीं लिया। 'अट्टहास' पत्रिका के माध्यम से उन्होंने व्यंग्य लेखन को एक सशक्त मंच प्रदान किया। उनके जाने के बाद कल्लू मामा की कहानी अधूरी रह गई, और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उनकी विरासत को आगे कौन बढ़ाता है।

शोकाकुल भीड़ की व्यवस्था नहीं हो गई थी।

डायरी में आगे लिखा गया कि अनूप जी ने हिंदी के सुप्रसिद्ध पत्रकार एवं हरिशंकर परसाई की परम्परा के अनुरूप राजनैतिक विषयों पर बेबाक व्यंग्य खुद भी लिखा और कल्लू मामा को भी लिखने का मौका दिया। पता नहीं कि परसाई के लेखन पर समाजवादी मूर्ख कितने खफा हुए। उन्होंने लिखा था कि आज मेरा मन संसोपा हो रहा है। आसमान में बादल छाए है, चलो संसद की कार्यवाही ठप करा दे।

डायरी में अनूप जी की धरती से विदा होने की तारीख मंगलवार, 21 जनवरी 2025 दर्ज है। फिर भी कल्लू मामा उनको खोज रहे है। कल्लू मामा को तो दिल्ली में राष्ट्रवादी ढूंढ रहे है कि कैसे उसके मुंह पर मजबूत रस्सी बांध कर उसका रेंकना बंद कराए।

डॉक्टरों ने उनका गंभीरता से इलाज शुरू कर दिया है। दिन में चार बार मनकी बात की रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है, लेकिन वह मौका लगते ही अनूप जी का कांव कांव पढ़ने लगते है। इसके अलावा वह कई बार अट्टहास पढ़ते पाये गये हैं।

इसके लिए राष्ट्रवादियों ने खुफिया पुलिस से भी जांच कराई है। डायरी में आगे लिखा हैं कि अनूप जी को सुप्रसिद्ध लेखक ठाकुर प्रसाद सिंह ने ट्रेंड किया था। ठाकुर प्रसाद सिंह ने यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में टॉप किया था। उनके गुरू अशोक जी थे, जिन्होंने 1935 में आई सी एस

कल्लू मामा की डायरी और अनूप श्रीवास्तव की विरासत

अनूप श्रीवास्तव जी ने न केवल व्यंग्य लेखन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि नए लेखकों को भी प्रोत्साहित किया। उनके मार्गदर्शन में कल्लू मामा जैसे पात्रों ने अपनी पहचान बनाई। लेकिन राष्ट्रवादी व्यवस्था में आज कल्लू मामा भटक रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस लेख में उनकी डायरी के अंशों के माध्यम से अनूप जी की लेखन यात्रा, उनके संघर्ष और हिंदी पत्रकारिता में उनके योगदान को बेबाकी से प्रस्तुत किया गया है।

छोड़ कर पत्रकारिता का कठिन मार्ग पकड़ा था।

यह सोच का विषय है कि क्या अनूप जी को राष्ट्रवादी बनकर अपने और कल्लू मामा के जीवन में खुशियां नहीं भरनी चाहिए थी।व्यंग्य लेखन में वह इतना रच बस गए थे कि उन्होंने कालांतर में अट्टहास पत्रिका मासिक का प्रकाशन किया और न अपने लिए कुछ किया और न ही हमारे जैसे मित्रो के लिए।

अट्टहास पत्रिका भले ही देश भर के रचनाकारों का सबसे बड़ा मंच बन गया हो पर अनूप जी ने जीवनभर कष्ट उठाया और अपने सीमित साधनों के साथ अट्टहास का जीवनभर संपादन किया। हाल ही में पत्रिका की 25 वीं जयंती मनाई गईं थी।

अनूप जी ने अपने लेखन में किसी को भी नहीं बक्शा। उनके प्रशंसकों में देश के प्रायः सभी राजनेता थे, जिसमे प्रमुख थे हिंदी के कवि एवं लेखक पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित नारायणदत्त तिवारी, मुलायम सिंह यादव, राजनाथ सिंह, आदि। उनकी बेबाक निष्पक्ष टिप्पणी के सभी कायल रहे है। उन्होंने प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री किसी से भी कोई निजी एहसान नहीं लिया ।

लेकिन आज की राष्ट्रवादी व्यवस्था में कल्लू मामा भटक रहे है। क्या उनके जैसे लोगो को अपनी बात कहने का जीने का अवसर मिलेगा।

****

लेखक : वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनैतिक विश्लेषक है।

हास्य व्यंग

क्यों केवल भारत में ही होता है पुर्नजन्म

केवल भारतीयों का ही पुनर्जन्म क्यों होता है (कर्म प्रणाली के आधार पर) देवदूत गेब्रियल प्रभु के पास आये और बोले: "मुझे आपसे बात करनी है।

"हमारे यहां स्वर्ग में कुछ भारतीय हैं और वे समस्याएं पैदा कर रहे हैं।

"वे पर्ली गेट्स पर झूल रहे हैं, मेरा हॉर्न गायब है, वे अपने सफेद लबादों की जगह डोल्से एंड गबाना की साड़ियां पहन रहे हैं, वे रथों की जगह मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू चला रहे हैं, और वे अपनी गाड़ियां रियायती दामों पर बेच रहे हैं।

"वे स्वर्ग की सीढ़ियों को साफ या स्वच्छ रखने से इनकार करते हैं, क्योंकि वे सीढ़ियों के बीच में बैठते हैं, समोसे खाते हैं और चाय पीते हैं।

"वे अनुशासन में विश्वास नहीं करते, और लाइन में घुसने के लिए अपना रास्ता बनाते हैं!"

भगवान ने कहा, "ओह, भारतीय तो भारतीय ही हैं! स्वर्ग मेरे सभी बच्चों का घर है। अगर आप असली समस्याओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो शैतान को फ़ोन करें।"

गेब्रियल ने सैतान को फोन किया।

शैतान ने फोन उठाया, "हुल्लो! शैतान यहाँ है।"

गेब्रियल - "क्या आपको नरक में भारतीयों से कोई समस्या है?"

सैतान कहता है: "मुझे खेद है, गैब्रियल, मैं अभी बात नहीं कर सकता। "मैं बहुत बुरा समय बिता रहा हूँ!

"ये भारतीय एयर कंडीशनिंग लगा रहे हैं और आग को बुझाकर नरक को रहने के लिए एक आरामदायक जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उन्हें चिलचिलाती गर्मी में रखने के लिए है!

"चूंकि वे इतने तकनीकी जानकार हैं, इसलिए वे स्वर्ग और नर्क के बीच, मेरे और ईश्वर के बीच टेलीफोन और इंटरनेट कनेक्शन बना रहे हैं !!

"उन्होंने संकटग्रस्त लोगों के लिए एक सामाजिक सेवा नेटवर्क शुरू किया है, और दूसरों को समझाने में वे बहुत अच्छे हैं।

“कुछ लोगों ने भजिया, खांडवी, ढोकला, चकली, पाउ-भाजी, इडली-डोसा, समोसा, बर्फी, कुल्फी के साथ चाय की दुकान खोली है, जिसे मैंने रोकने की कोशिश की।

"वे सभी को भ्रष्ट कर रहे हैं और मेरे कर्मचारियों को रिश्वत दे रहे हैं।

"मुझे नरक में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में कठिनाई हो रही है।

"वे कभी शिकायत नहीं करते, क्योंकि यह स्थान उस स्थान से बेहतर लगता है जहां से वे आये थे!

"इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, "हे ईश्वर, कृपया, जैसे ही भारतीय आएँ, उन्हें पृथ्वी पर वापस भेज दीजिए - पुनर्जन्म के लिए।"

तो अब आप जान गए होंगे - "क्यों केवल भारतीय ही पुनर्जन्म लेते हैं.."

****

सुविचार

मेहनत इतनी ख़ामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे।

****

सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है, और मेहनत करने वालों के लिए दिन।

असफलता सिर्फ यह बताती है कि सफलता की कोशिश अभी अधूरी है।

****

जो वक्त के साथ बदलता नहीं, वक्त उसे बदल देता है।

अपनी काबिलियत पर इतना काम करो कि किस्मत भी सलाम ठोकने पर मजबूर हो जाए।

****

कठिनाइयाँ वो सीढ़ियाँ हैं जो सफलता की ऊँचाइयों तक ले जाती हैं।

सुन्दर फूलों का रहस्यमय गुच्छा

श्री दिनेश वर्मा, भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी हैं। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अपना समय लेखन को समर्पित किया और वर्ष 2016 में उनकी पहली किताब 'माई टाइम्स माई टेल्स' में प्रकाशित हुई जो 27 कहानियों का संग्रह है। पुस्तक का हिंदी अनुवाद "मेरे समय की मेरी कहानियाँ" के रूप में हुआ। प्रस्तुत कहानी उसी संग्रह से ली गयी है। - संपादक

****

"देखिए, वह हमारे घर पर कोई टोना टोटका कर रही है।" यह कहते हुए मेरी पत्नी गुस्से से तमतमाई हुई सुबह सुबह कमरे में आईं। मैं बड़ी गहरी नींद में सो रहा था। उनकी क्रोधपूर्ण तेज़ आवाज़ सुनकर मैं झटके से उठ बैठा। आँखे मलते हुए, किसी प्रेत के समान चलकर, उन के पीछे पीछे मैं अपनी बालकोनी में पहुँचा जहाँ एक रंगीन खूबसूरत कागज़ में लिपटे कुछ फूल रंगीन डोरे से बन्धे हुए पड़े थे। मेरी पत्नी ने ऊपर की तरफ देखकर संकेत किया कि कोई और नहीं था बल्कि ऊपर वाले फ्लैट में रहने वाली महिला का काम था। मेरी काफी कोशिश के बाद वह शान्त हो पाईं।

हम इस घटना को करीब करीब भूल चुके थे। लेकिन वही घटना पंद्रह दिनों बाद फिर सुबह के उसी समय घटित हो गई जब मेरी पत्नी अपने लाडले बच्चों के समान फूलों और पौधों के लालन पालन में व्यस्त थी। अबकी बार उन्हें शान्त कर पाना मेरे बस के बाहर था। उनके चेहरे पर डर, पीड़ा और रोष के चिन्ह देखकर मैं खुद भी डर गया था। भला अपने बच्चों के प्रति किसी की दुर्भावना वह कैसे बर्दाश्त कर पातीं। मैं उन्हें यह समझा कर शान्त कर पाया कि शायद पूजा के फूल ऊपर वालों ने अपनी दीवार पर रख दिए होंगें और वहाँ से वे हमारी बालकोनी में गिर गए। सच बात तो यह थी कि मुझे लड़ाई झगड़े से बहुत डर लगता था और पड़ोसियों से अच्छे सम्बन्ध बनाए रखने की तो मेरी हमेशा से ही कोशिश रही थी। मेरी समझ में यह ऐसा विषय था भी नहीं जिसपर बात को आगे बढ़ाया जाता। इसलिए मन ही मन मैंने भगवान को धन्यवाद दिया और राहत की साँस लेते हुए प्रार्थना कि 'हे! प्रभु, अब वह घटना फिर से मत घटने देना।' लेकिन घटना को तो घटना था सो वह घट कर रही।

दिल्ली के बहुमंज़िला फ्लैटो में रहने वालों का अपने पड़ोसियों को चुन्ने में कोई हाथ नहीं होता। जहाँ एक अच्छी, सुशिक्षित, शरीफ और अनुशासित पड़ोसी परिवार भगवान का वरदान होता है, वहीं यदि पड़ोसी लड़ाका और शैतानी तबियत का हो तो आपके पास सिवाए उस परिवार को सहन करने के और कोई चारा नहीं होता। मेरा यह ख्याल है कि बहुमंज़लीय मकानों में सहन करने के सिवा और कोई चारा नहीं होता। और सबसे एहम तरीका है हर किस्म की बेवकूफी को सूझबूझ के साथ निपटाते रहना। और यदि आप ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि आप भी लड़ाका तबियत के हैं तो समझ लीजिए कि रोज़ ही नए नए बखेड़े खड़े होते रहेंगे और मज़ा लेने वालों को हंसने का मसाला मिलता रहेगा।

जहाँ तक मेरा सवाल है मैं जितना भी धन्यवाद करूं भगवान का वह कम है। जब से मैं अपने परिवार सहित दिल्ली के फर्स्ट फ्लोर के फ्लैट में शिफ्ट हुआ तब से सिवाए एक परिवार को छोड़कर, जो हमारे ऊपर वाले फ्लैट में अपनी स्कूल पढ़ती बेटी के साथ रह रहा था, और सारे परिवार बड़े सज्जन और सहनशील स्वभाव के थे। हां, यह परिवार ज़रूर कुछ अलग थलग सा था।

कभी कभी सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते मैं उस परिवार से टकरा जाया करता था और उस पूरे परिवार को देखकर मुझे ऐसा लगा कि अधेड़ उम्र के घर के मालिक मस्त मौला किस्म के तो थे मगर मिलनसार बिलकुल भी नहीं थे। उनकी पत्नी, जिनकी उम्र करीब तीस साल की रही होगी, देखने में भारी भरकम शरीर की थी। मुझे उनकी आँखों में अजीब सी चमक दिखाई दी

जिससे ये अंदाज़ा लगता था कि वह दो लोगों को बड़ी आसानी से आपस में लड़वा सकती थीं। यही नहीं शायद उन्हें अपने इस गुण पर काफी नाज़ था। हमारा उनसे सम्बन्ध केवल नमस्ते तक ही सीमित रहा। ऐसे सम्बन्धों के होते हुए यदि मेरी पत्नी को ऊपर वाली महिला पर शक पैदा हो गया था तो क्या ताज्जुब की बात थी। शक तो छोड़िये, उन्हें पूरा विश्वास था कि यह उन्ही का काम था।

मैंने लगातार परमात्मा से प्रार्थना की कि वह इस प्रकार की घटना अब घटित न होने दें लेकिन मेरी प्रार्थना में शायद कोई कमी रह गई थी। मैं फिर एक बार तूफ़ान में घिर गया। अखबार पढ़ते हुए बालकोनी में बैठकर मैं सुबह की चाय के घूंट ले रहा था कि यकायक मेरी नज़र एक तरफ पड़े फूलों के गुच्छे पर पड़ी जिसे देखकर मुझे बहुत ज़ोर का झटका लगा। थोड़ी देर तक तो मैं सुन्न बैठा रहा। फिर मेरा दिमाग क्रोध से भन्नाने लगा। हालाँकि मुझे टोना टोटका जैसी चीज़ों पर कभी भी विश्वास नहीं था लेकिन फूलों का इस तरह बार बार गिरना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मेरे लिए तो यह विचार ही असहनीय था कि कोई मेरे बच्चों पर बुरी नज़र डाल रहा था। मेरी पत्नी की बड़बड़ाहट ने मेरे गुस्से को और हवा दे डाली। मुझे अपने आप पर काबू कर पाना मुश्किल हो गया । गुस्से से भुनभुनाता हुआ, सीडियों को दो छलांगों में पार कर, मैं ऊपर वाले फ्लैट में जा पहुँचा। मैंने दरवाज़े को धक्का दिया और वह खुलता चला गया। मैंने अपने आप को उनके बाहर के कमरे में खड़ा हुआ पाया जिसे लोग ड्राइंग रूम कहते हैं। मेरा चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। जिस्म थरथर कांप रहा था। कमरे में बैठे हुए सज्जन एकदम हड़बड़ा कर उठ खड़े हुए। वह मेरे यकायक अंदर घुस आने पर आश्चर्य चकित थे। मैं बस इतना ही कह पाया, "देखिये, ये बालकोनी में फूल...... वह तो खामोश खड़े विचलित दृष्टि से स्थिति समझने का प्रयत्न करते रहे, लेकिन इतने में उनकी पत्नी करीब करीब रोती हुई आ गईं और उन्होंने कसम खाते हुए कहा कि उन्हें इससे कुछ लेना देना नहीं था। मेरी पूरी बात बताने से पहले ही उनकी समझ में सारी बात के आ जाने से मेरा शक विश्वास में परिवर्तित हो गया। लेकिन उन महिला को रो रो कर अपना बचाव करता देख कर मैं चुपचाप बिना कुछ कहे वापिस लौट आया। मैंने सोचा कि चलो किसी तरह इस कहानी का अंत तो हुआ।

दिन गुज़रते गए और यह कहानी हम भूल से गए थे। कई हफ्ते बाद एक सुबहू जब मेरी पत्नी पौधों में पानी डाल रही थीं तो उन्हें कुछ पत्ते और डालियाँ सूखी हुई दिखाई दीं। ये उनके लिए बहुत ही चिन्ता की बात थी। वह फौरन किसी माली की तालाश में लग गई। वह बालकोनी से झांक झांक कर नीचे की सड़क पर देखने लगी जहाँ माली भी ग्राहक की तालाश में घूमा करते थे। एक घंटे बेचैनी से इंतज़ार के बाद एक माली हमारी बालकोनी में आ गया और वह माली पौधों को ऐसे देखने लगा जजैसे डॉक्टर मरीज़ को देखते हैं। मेरी पत्नी चिन्तित नज़रा सी पौधों को रही थी जैसे बीमार को तीमारदार देखते है। माली ने उन मुर्झाए पौधों को हरा-मेरो देख की कई तरीके सुझाए। हमारी पत्नी ने जब उस से नए पौधे लगाने कोको हरा-भरा करने के कई तमे चाँका कर रख दिया। उसने कहा कि उसने बालकोनी में जो सैंपल डाले थे वह उसी में से कोई भी छांट के नया पौधा लगा सकती थीं। ओह! हे भगवान! तो ये कहानी थी। फूलों के गुच्छे का रहस्य जब खुला तो हमें एक झटका लगा। हमारी पत्नी गुमसुम खड़ी रहीं। मैं सारी कहानी की तह तक पहुँच पाने का प्रयत्न करने लगा जिसके कारण दो परिवारों में झगड़ा होते होते बचा था।

मैंने जब माली से सवाल जवाब किए तो उसने बताया कि अपनी विक्री के लिए वह कॉलोनी की बालकोनियों में नए नए फूलों के सैंपल डालता रहा था एक अच्छे से कागज में बान्ध कर और बहुत से परिवार उन सैंपल पर भरोसा भी कर रहे थे।

माली तो चला गया लेकिन हम खामोश बैठे अपनी बेबकूफी पर अपने आप को कोसते रहे। वह तो अच्छा हुआ कि मैंने मामले को आगे नहीं बढ़ाया था। शायद इसी कारण हमारा आत्मसम्मान बचा रह गया।

****

समय की पुकार गंगा जमनी तहजीब

डॉ सतीश मिश्रा

मीडियामैप के जनवरी अंक में प्रकाशित अंदाज़-ए-लखनऊ सप्लीमेंट को मिली प्रतिक्रिया गर्मजोशीपूर्ण और सकारात्मक रही है। हमें उन दोस्तों से अधिक से अधिक संपर्क करना चाहिए, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से हमारे देश को मुक्त करने के लंबे संघर्ष के बाद उभरे भारत के विचार के प्रति बढ़ते खतरों के बारे में हमारी साझा चिंताओं को समझते हैं। विशेष रूप से महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम ने इस विचार को आकार दिया, उसे अत्यंत सावधानी से पोषित किया और इसे एक ठोस ढांचे में विकसित कर हमारे संविधान में स्थान दिया।

हमें विश्वास है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि भारत की अवधारणा 'अवध की संस्कृति' पर आधारित है, जिसे 'गंगा-जमुनी' जीवनशैली के रूप में भी जाना जाता है।

हम गंगा-जमुनी तहज़ीब को बचाने और संरक्षित करने के हमारे मिशन के लिए आपका समर्थन चाहते हैं, जो जाति, पंथ या आस्था से परे एक-दूसरे के प्रति सम्मान की भावना से प्रेरित है। आप किसी भी क्षमता में हमारे साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित हैं, जैसे कि पाठक, लेखक या समर्थक। आप सुझाव दे सकते हैं और इस मुद्दे को भारत और विदेश में अपने दोस्तों तक पहुँचा सकते हैं।

हम आपको हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को मजबूत करने और उसकी रक्षा करने के हमारे अभियान का समर्थन करने के लिए आमंत्रित करते हैं, ताकि हम एकजुट होकर समृद्ध हो सकें, राष्ट्र के बीच अपना प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर सकें और एक न्यायपूर्ण आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

****

लेखक : मीडिया मैप के संयुक्त संपादक हैं।

लखनऊ काफी हाउस और बैठकबाजी की अनोखी विरासत

प्रदीप कपूर

लखनऊ का काफी हाउस केवल एक चाय-कॉफी की जगह नहीं था; यह शहर की सांस्कृतिक, साहित्यिक और राजनीतिक आत्मा का केंद्र था। यहाँ हिंदी साहित्य के दिग्गज जैसे यशपाल, अमृत लाल नागर और भगवती चरण वर्मा अपने विचारों से माहौल को रोशन करते थे। इनकी उपस्थिति इतनी आकर्षक थी कि लोग इन्हें सुनने के लिए घंटों इंतजार करते थे।

वरिष्ठ पत्रकार विद्यासागर ने बताया कि मजाज़ और सलाम मछलीशहरी जैसे शायरों की दिलचस्प बहसें भी काफी हाउस की शोभा बढ़ाती थीं। मजाज़ के शेर सुनने के लिए महिलाओं की भीड़ बाहर इंतजार करती थी। राजनीति और पत्रकारिता से जुड़े नामचीन लोग, जैसे एम. चेलापति राव और राजनाथ सिंह, यहाँ आकर राजनीतिक नब्ज़ टटोलते थे।

काफी हाउस में छात्र आंदोलनों और सामाजिक बदलाव की नींव रखी जाती थी।

सीपीआई के नेता अतुल अनजान, जब लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र नेता थे, तो उनके साथ कई युवा नेता यहाँ चर्चाएं करते थे।

लखनऊ के पूर्व मेयर डॉ. दाऊजी गुप्ता ने बताया कि काफी हाउस केवल बहस का स्थान नहीं था, यह विचारों के आदान-प्रदान और एकजुटता का प्रतीक भी था। लालजी टंडन जैसे राजनेता ने इसे "राजनीतिक पाठशाला" कहा, जहाँ विचारधाराओं का मतभेद तो था, पर मनभेद नहीं।

लखनऊ के अन्य सांस्कृतिक अड्डे, जैसे बेनबोज रेस्टोरेंट और अमीनाबाद का अब्दुल्ला होटल, भी साहित्यकारों और नेताओं के मिलने-जुलने के स्थल थे। आज भी इन जगहों की विरासत और यादें लखनऊ की गंगा-जमुनी तहज़ीब की गवाही देती हैं।

****

लेखक वरिष्ठ पत्रकार है

ऐसे भी होते थे हमारे प्रधानमंत्री

पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ऐसे राजनेता थे जो स्वयं अपने पत्रकार मित्रों के घर जाना उनके साथ काफी हाउस में बैठकी करना पसंद करते थे।

चंदशेखर जी मेरे पिता बिशन कपूर, जो ब्लिट्ज के ब्यूरो चीफ थे, के मित्र थे और उस जमाने में अक्सर काफी हाउस से पैदल ही हमारे घर चले आते थे। उनके साथ ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी और पारस नाथ मिश्र रहते थे।

एक बार पूर्व प्रधान मन्त्री चंद्रशेखर जी लखनऊ आए तो हम उनसे मिलने वीवीआईपी गेस्ट हाउस मिलने गए तो अपने पुराने पत्रकार मित्रो के बारे में पूछने लगे। तभी उनको हमउम्र पत्रकार विद्यासागर जी की याद आई तो हमने बताया की वे घर पर रहते है।

चंद्रशेखर जी को याद था कि वे लॉरेंस टैरेस में रहते हैं। चंद्रशेखर जी ने कहा कि विद्यासागर जी को आप बता दीजिए और हमको साथ लेकर उनके घर चला जाय।

हम शाम को पूर्व प्रधानमंत्री के साथ विद्यासागर जी के घर पहुंचे तो दोनों पुराने दोस्त गले मिले। फिर पैर उपर कर जो आराम से बैठ कर चंद्रशेखर जी ने लगभग दो घंटे मुलाक़ात की और हरी मटर के साथ काफी पी कर उनको बहुत मजा आया। पुराने दौर मित्रो चंद्रशेखर और विद्यासागर के वार्तालाप का हमने भी मजा लिया और अपना ज्ञान बढ़ाया।

चंद्रशेखर (1927 – 2007)

विद्यासागर जी के घर चंद्रशेखर जी बताया की दिल्ली में भी वें अक्सर ब्लिट्ज के राघवन और गिरीश माथुर के घर काकानगर चले जाते थे। विद्यासागर जी से मिलकर कार में वापस लौट रहे थे तो चंद्रशेखर जी कहा कि पुराने मित्र से मिलकर उनका लखनऊ आना सार्थक रहा।

इसी तरह एक बार पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर लखनऊ आए और यूपी प्रेस क्लब में पत्रकारों के साथ भोजन लिया। बाद में अंदर के कमरे में अपने वक़्त के पत्रकारों।हमिदी बे, एस एन घोष तरुण कुमार भादुड़ी रमेश पहलवान चंद्रोदय दीक्षित बिशन कपूर राम उग्रह सलाहुद्दीन उस्मान नेशनल हेराल्ड के बहल साब, सुरेन्द्र चतुर्वेदी एस सी काला साहब को खूब याद किया। - **प्रदीप कपूर**

****

मक्खन मलाई का जादू: जुबान के साथ आत्मा में भी घुल जाती है मिठास

ज़ेबा हसन

लखनऊ की नवाबी संस्कृति का एक अनमोल हिस्सा, मक्खन मलाई, जिसे मुंह में रखते ही हल्की मिठास का अहसास होता है, किसी भी खाने वाले को अपनी ओर खींच लेता है। खासकर जाड़े के मौसम में चौक की गलियों में मिलने वाला यह मक्खन मलाई अपने स्वाद से न केवल लखनऊवासियों, बल्कि फिल्मी दुनिया के सितारों को भी दीवाना बना चुका है। शिल्पा शेट्टी से लेकर विद्युत जामवाल जैसे फिटनेस फ्रीक भी इस लज़ीज़ मिठाई का आनंद ले चुके हैं। हालांकि, इसका नाम मक्खन मलाई है, लेकिन इसमें न तो मक्खन होता है और न ही मलाई। दरअसल, यह दूध के झाग से तैयार किया जाता है, जिसे फेट कर और दबा कर गाढ़ा किया जाता है। पुराने लखनऊवाले इसे निमिश भी कहते हैं, और उन्नाव- कानपुर में इसे मलाइय्यो के नाम से जाना जाता है।

लखनऊ में चौक का गोल दरवाजा मक्खन मलाई का सबसे प्रसिद्ध ठिकाना है। पीतल के परात में सजा यह मक्खन मलाई केसर के हल्के पीले रंग में रंगी होती है, और ऊपर से बादाम, पिस्ता और चांदी का वर्क डाला जाता है। इसका स्वाद सिर्फ मुंह को नहीं, बल्कि दिल और आत्मा को भी सुकून देता है। इसे खाने के लिए आप दौने में भी खा सकते हैं या फिर मिट्टी की हांड़ी में पैक करवा सकते हैं, हर रूप में यह स्वाद लाजवाब होता है।

मोनू प्रसाद, जो पिछले 20 सालों से चौक में मक्खन मलाई बेच रहे हैं, बताते हैं कि इस मिठाई को तैयार करने की प्रक्रिया में विशेष मेहनत और समय लगता है। वे कहते हैं कि अटल जी भी एक बार यहां आए थे और इस मक्खन का स्वाद लिया था। मक्खन को बनाने के लिए सुबह चार बजे से सात बजे तक मथाई

की प्रक्रिया शुरू होती है। जितनी मथाई होगी, मक्खन उतना हल्का और स्वादिष्ट बनेगा। मथने के लिए लकड़ी की खास मथानी का उपयोग किया जाता है। सुबह सात बजे मक्खन तैयार होकर चौक आता है, और जब यह खत्म हो जाता है, तब और लाया जाता है। मोनू बताते हैं कि उनके दादा इस मक्खन को ओस में रखकर तैयार करते थे, लेकिन अब इसे आग पर पकाया जाता है। 50 किलो मक्खन तैयार करने के लिए 50 लीटर दूध और 25 किलो क्रीम का उपयोग होता है। दूध और क्रीम को आधे घंटे तक आग पर पकाया जाता है, फिर इसे मथने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसमें चीनी या महीन पिसी मिश्री डाली जाती है, और फिर दो ग्राम केसर रंग और स्वाद के लिए डाला जाता है। इसे ठंडा करने के लिए रात भर खुले में रखा जाता है। इस प्रक्रिया में चार से पांच घंटे लगते हैं, और रात के दो से तीन बजे तक मक्खन तैयार हो जाता है।

मक्खन मलाई का जन्म कब और कहां हुआ, इसकी सटीक जानकारी नहीं मिलती, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह शाही बावर्चीखाने में बादशाह अकबर के समय में इजाद हुआ था। फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे भी इस लखनऊ की मिठाई का स्वाद चख चुके हैं। 2019 में शिल्पा शेट्टी ने लखनऊ में शूटिंग के दौरान मक्खन मलाई का आनंद लिया और इंस्टाग्राम पर इसका वीडियो पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था, "रविवार का आनंद, नवाबी अंदाज में।" पंकज त्रिपाठी, सौरभ शुक्ला, नीतू चंद्रा और परिणीति चोपड़ा जैसे सितारे भी इस मिठाई की तारीफ करते हैं।

मक्खन मलाई, लखनऊ की शाही मिठाई है, जो न केवल यहां के निवासियों को, बल्कि दुनिया भर से आने वाले यात्रियों और सितारों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। इस मिठास का राज न केवल इसके स्वाद में, बल्कि इसके विशेष बनाने की प्रक्रिया और मेहनत में भी छिपा है।

****

लेखिका : मीडिया मैप की लखनऊ संवाददाता है।

सुरेंद्र चतुर्वेदी (1929 -1977)

सुरेन्द्र चतुर्वेदी की स्मृति में

पत्रकार का धर्म, वे शब्द नहीं, अर्थ बदलते हैं।
वे तथ्य नहीं, सत्य बदलते हैं।
वे घटना नहीं, इतिहास बदलते हैं।
वे खबर नहीं, समाज बदलते हैं।
वे मिट्टी नहीं, स्वप्न बदलते हैं।
वे कलम नहीं, कल बदलते हैं।
तभी तो...
अंधेरे से उजाले का संपूर्ण संवाद
पत्रकार के शब्दों में संजोया जाता है।

RNI NO. : UPHIN/2016/68336

See Media Map Website

Website link: www.mediamap.co.in

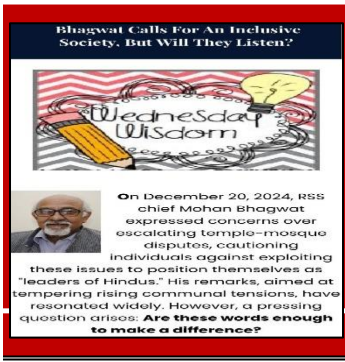
Bhagwat Calls For An Inclusive Society, But Will They Listen?

On December 20, 2024, RSS chief Mohan Bhagwat expressed concerns over escalating temple-mosque disputes, cautioning individuals against exploiting these issues to position themselves as "leaders of Hindus." His remarks, aimed at tempering rising communal tensions, have resonated widely. However, a pressing question arises: **Are these words enough to make a difference?**

Dr Man Mohan Singh : A Lone Warrior Who Unshackled Indian Economy

Gopal Misra

New Delhi | Monday | 30 December 2024

Few in India could have ever imagined that a soft-spoken academic, Dr Man Mohan Singh, would be transforming India, first as a finance minister and later as the Prime

India Keen For Early Improvement In Ties With Dhaka

Prof Shivaji Sarkar

New Delhi | Monday | 16 December 2024

India and Bangladesh have entered a pivotal phase in their diplomatic relationship amidst shifting regional political dynamics. On December 9, Indian

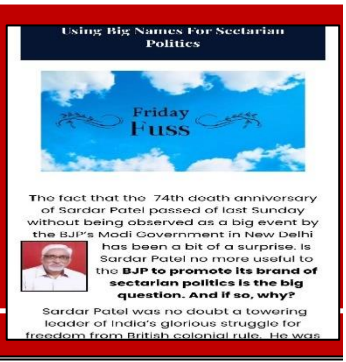
Using Big Names For Sectarian Politics

The fact that the 74th death anniversary of Sardar Patel passed of last Sunday without being observed as a big event by the BJP's Modi Government in New Delhi has been a bit of a surprise. Is Sardar Patel no more useful to the **BJP to promote its brand of sectarian politics is the big question. And if so, why?**

Sardar Patel was no doubt a towering leader of India's glorious struggle for freedom from British colonial rule. He was

View Media Map YouTube

Media Map News

vol- 1002, 13 jan 25, ep- 59 : महाकुंभ में संत तीर्थयात्री सीवरेज के पानी में नहाने...

vol-1002, 11 jan 25, ep- 58 : महाकुंभ में कई वेशभूषा में बाबा

vol-1002, 9 jan 25, ep-57: मुस्लिम भी इलाहाबाद पुर्ण महाकुंभ में कल्पवास कर...

vol- 1002, 4 jan 2025, ep- 56: Media Map: Youtube meeting

आर्थिक सहयोग की अपील

उदार लोकतंत्र और गैर-सांप्रदायिक विश्वास के दर्शन से जुड़ा, मीडियामैप समाचार नेटवर्क एक गैर-व्यावसायिक संगठन है। हम आप जैसे गंभीर और समझदार पाठकों को संबोधित करना चाहते हैं। वरिष्ठ मीडियाकर्मियों के समूह द्वारा किया गया यह एक स्वैच्छिक प्रयास है, जिसका किसी राजनीतिक, सामाजिक या व्यावसायिक समूह से कोई संबंध नहीं है। मीडिया मैप के प्रकाशन को निरंतर व सुचारु रूप से जारी रखने हेतु आपका सहयोग आवश्यक है।

- ***State Bank of India***
- ***Account No. 43812481024***
- ***IFSC # SBIN0005226***
- ***प्रस्तुत QR कोड को स्कैन करें।***

प्रकाशक

MBKM Foundation, एक पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन

पंजीकृत कार्यालय

फ्लैट नंबर: 2332, सेक्टर-डी, पॉकेट-2, वसंत कुंज, दक्षिण दिल्ली

Advt.

Please stay with us and explore the beauty of the surrounding areas .

Scholars Destination

PLEASE CONTACT

9045005700 | 9910322682 | www.sdmotel.com | info@sdmotel.com